epaper.dehatsandesh.com

3 ट्रैफिक पुलिस ने एक स्टंट बाइक सवार के खिलाफ की कार्रवाई

5 प्रगगनानंदा और गुकेश ने आर्मागेडन ने दर्ज की जीत

8 जंगलोट दौरे पर विधायक, जल संकट समाधान को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

न्यूनतम 26 मौसम जम्मू अधिकतम 40

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-127 जम्मू तवी, बुधवार 27 मई, 2026 मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये पृष्ठ -8

घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव के अध्ययन के लिए केंद्र ने बनाई उच्चस्तरीय समिति

घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला असामान्य जनसांख्यिकीय बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह विषय राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है

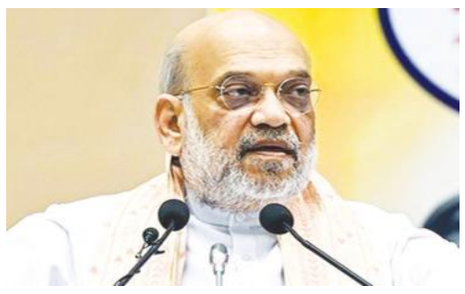

नई दिल्ली, 26 मई । केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने तथा उससे निपटने के उपाय सुझाने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को 'हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन' की घोषणा की थी, जिसे 11 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी।

सरकार द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। समिति में जनगणना आयुक्त के अलावा दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि सदस्य होंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फॉरेनर्स-1) समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। समिति को एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय इसके कार्यकाल को अधिकतम छह महीने तक बढ़ा सकेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला असामान्य जनसांख्यिकीय बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह विषय राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक संरचना और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है।

सरकार के अनुसार, यह समिति देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलावों का वैज्ञानिक आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और आवश्यक नीतिगत, विधायी तथा प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक उपाय सुझाएगी।

समिति जनसांख्यिकीय बदलावों से उत्पन्न चुनौतियों, विशेषकर घुसपैठ, सीमा पार गतिविधियों, असामान्य बसावट पैटर्न और संगठित प्रवासन जैसे कारणों का अध्ययन करेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का भी विश्लेषण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त समिति अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध तंत्र विकसित करने संबंधी सुझाव देगी। सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए संस्थागत व्यवस्था की सिफारिश भी समिति करेगी।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करने के साथ-साथ समिति इस विषय से जुड़े अन्य आवश्यक उपायों की भी अनुशंसा कर सकेगी।

चीन-पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर का जिक्र, भारत ने जताया विरोध

नई दिल्ली, 26 मई । भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के गैर जरूरी संदर्भ को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि संबंधित पक्षों को भारत की इस संदर्भ में जग जाहिर और निरंतर बनी हुई स्थिति का पता है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। इस विषय पर किसी अन्य देश को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रवक्ता ने कहा कि तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) परियोजनाओं के संबंध में हम अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान के इन क्षेत्रों पर अवैध और जबरन कब्जे को सुदृढ़ या वैध ठहराने के किसी भी प्रयास का दृढ़तापूर्वक विरोध और अस्वीकार करते हैं। सीपीईसी के कुछ हिस्से भारत की संप्रभुता वाले क्षेत्र में आते हैं और यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। यह बात पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को कई बार स्पष्ट रूप से बता दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने चीन और पाकिस्तान के बीच तथाकथित 'सीमा पार जल संसाधन सहयोग' के संदर्भ भी देखे हैं। दोनों देशों की सीमा आपस में नहीं जुड़ती है। ऐसे में तथाकथित 'सीमा पार जल संसाधन सहयोग' का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच तथाकथित 1963 के सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है।

उल्लेखनीय है कि चीन और पाकिस्तान ने मंगलवार को जारी संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर मुद्दे को 'इतिहास से बचा हुआ विवाद' बताया तथा इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत शांतिपूर्ण वार्ता से करने की बात कही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कल बैठक हुई थी।संयुक्त बयान में चीन और पाकिस्तान ने सीमापार जल संसाधनों पर सहयोग बढ़ाने की बात कही। दोनों देशों ने 'समानता और पारस्परिक लाभ' के सिद्धांतों के आधार पर जल प्रबंधन तथा जल संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर समन्वय जारी रखने पर सहमति जताई। बयान में किसी विशेष नदी, परियोजना या समझौते का नाम नहीं लिया गया।

खबर संक्षेप

भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फंसे कई यात्री

बारामुला, 26 मई। मंगलवार को उरी-बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिरी के धनखान इलाके के पास भारी भूस्खलन होने से इलाके में अफरा-तफरी और परेशानी का माहौल पैदा हो गया। भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह मलबे, पत्थरों और मिट्टी से भर गई जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। जानकारी के अनुसार पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक सड़क पर आ गिरा जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंच गईं। सड़क से मलबा हटाने का कार्य जल्द शुरू हो गया ताकि यातायात बहाल किया जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि स्थिति सामान्य होने तक इस मार्ग पर यात्रा करने से बचें। समाचार लिखे जाने तक किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं थी। वहीं प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

डोडा में गिरा निर्माणाधीन पुल, एक मजदूर की मौत

डोडा, 26 मई । डोडा जिले के गंडोह के गिल इलाके में मंगलवार दोपहर पीएमजीएसबाई प्रोजेक्ट के तहत बन रहा एक पुल अचानक कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान गिर गया। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 5 घायल मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा रेफर किया गया है। गंडोह के एसडीएम अरुण कुमार बुट्याल ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे पुल की शटरिंग अचानक गिर गई। उस समय साइट पर करीब 11 मजदूर काम कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद बचाव दल और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने पुष्टि की कि एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 5 घायल मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा रेफर किया गया है। बाकी घायल मजदूरों का स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस, एसओजी, मेडिकल टीमें और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं, जबकि साइट पर बचाव अभियान अभी भी जारी है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

सरकार ने 13 साल की देरी के बाद आईएफओएस में 32 अधिकारियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की

जम्मू, 26 मई। एक महत्वपूर्ण कदम में जम्मू-कश्मीर सरकार ने लगभग 32 अधिकारियों को भारतीय वन सेवा आईएफओएस में शामिल करने की लंबे समय से लंबित प्रक्रिया शुरू कर दी है जिससे 13 वर्षों से अधिक समय से जारी गतिरोध समाप्त हो गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वन विभाग एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा अनुमोदन और आगे की कार्रवाई के लिए जल्द ही केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एमओईएफ एंड सीसी को भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय से ताजा संचार के बाद प्रक्रिया में तेजी आई जिससे प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वन विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदा ने पुष्टि की कि विभाग आईएफओएस में अधिकारियों को शामिल करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। हम प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रहे हैं और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। सूत्रों से पता चला है कि जम्मू-कश्मीर के लगभग 32 अधिकारियों को प्रतिष्ठित अखिल भारतीय सेवा में शामिल होने की संभावना है जो कि एमओइएफ़ और यूपीएससी से मंजूरी के अधीन है। राज्य वन सेवा एसएफएस के गठन से संबंधित कानूनी विवादों और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण 2012 से प्रेरण प्रक्रिया निलंबित थी। सेवा नियमों के अनुसार आईएफओएस में 66 प्रतिशत पद यूपीएससी द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं जबकि 33 प्रतिशत राज्य वन सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षित हैं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय ने लंबित कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों के कारण चयन वर्ष 2012 के बाद जम्मू और कश्मीर के लिए पदोन्नति कोटा रिक्तियां तय नहीं की हैं। सूत्रों ने आगे बताया कि राज्य वन सेवा के गठन से संबंधित प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद 11 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया था।

जम्मू-कश्मीर में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की प्रगति की समीक्षा

डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स के साथ एग्रीस्टैक और यूएलआई एकीकरण पर दिया जोर, किसानों के कल्याण को बताया प्राथमिकता

श्रीनगर, मई 26। मुख्य सचिव अतल डुल्लू ने आज जम्मू-कश्मीर में भूमि अभिलेखों के चल रहे डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित राजस्व प्रशासन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) राजस्व, सचिव राजस्व, संभागीय आयुक्त जम्मू/कश्मीर, आयुक्त सर्वे एवं भूमि अभिलेख, महानिरीक्षक पंजीकरण, राज्य सूचना अधिकारी (एसआईओ) एनआईसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि सही और अद्यतन भूमि अभिलेख कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) तथा एग्रीस्टैक पहलों के साथ एकीकरण के जरिए किसानों को संस्थागत ऋण तक त्वरित पहुंच उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेखों का सफल डिजिटलीकरण सुशासन को मजबूत करने, सेवा वितरण में सुधार लाने और किसानों को लाभ एवं वित्तीय सेवाओं तक सहज पहुंच उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा। मुख्य सचिव ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे प्रमाणित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी लंबित म्यूटेशन शेष न रहे। उन्होंने आने वाले दिनों में तहसीलदारों, उप मंडल मजिस्ट्रेटों और अंततः उपायुक्तों द्वारा जमाबंदियों को फ्रीज करने के निर्देश भी दिए, ताकि प्रमाणिक और विश्वसनीय डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जा सके। रिकॉर्ड्स के सुधार और अद्यतन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव ने वित्तीय आयुक्त (राजस्व) के परामर्श से प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। ये अधिकारी जिलों को सहयोग प्रदान करेंगे और रिकॉर्ड्स के समयबद्ध सुधार एवं सत्यापन को सुनिश्चित करेंगे। एग्रीस्टैक के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि चिन्हित क्षेत्रों में डिजिटलीकरण पूरा होते ही इस प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए और इसे आरबीआई के यूएलआई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, ताकि किसानों को आसान ऋण सुविधा मिल सके।

गांधी नगर में एसओजी कर्मियों और संदिग्ध अपराधियों के बीच गोलीबारी

जम्मू, 26 मई । मंगलवार शाम जम्मू के गांधी नगर स्थित ग्रीन बेल्ट पार्क के पास जम्मू और कश्मीर पुलिस (जेकेपी) के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के कर्मियों और संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ छिड़ गई। पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने अपने खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एसओजी वाहन को टक्कर मारकर और गोलीबारी करके भागने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि एसओजी कर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की और इलाके को सुरक्षित कर लिया। पुलिस ने आगे बताया कि अतिरिक्त बल मौके पर भेजा गया है और अभियान अभी भी जारी है। 26 मई 2026 को शाम लगभग 6 बजे गांधी नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम एसओजी दल के साथ संदिग्ध अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए गांधी नगर स्थित ग्रीन बेल्ट पार्क के पास मिनी मार्केट क्षेत्र में गई। ऑपरेशन के दौरान, संदिग्धों ने भागने का प्रयास किया और जानबूझकर अपनी गाड़ी एसओजी की गाड़ी से टकरा दी यह बात पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कही। इसके बाद संदिग्धों ने पुलिस दल पर गोलीबारी की। अपनी सुरक्षा और जान के खतरे को रोकने के लिए, एसओजी कर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। इलाके को तुरंत सुरक्षित कर लिया गया और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया

कठुआ में मिला ड्रोन, सुरक्षा कड़ी

जम्मू, मई 26 । जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में एक ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात कठुआ जिले के हटली क्षेत्र में गोविंदसर रेलवे स्टेशन रोड के पास यह ड्रोन बरामद किया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील केसर ने पत्रकारों से कहा, रात को सूचना मिली थी कि हटली थाना क्षेत्र में ड्रोन देखा गया है। सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन को कब्जे में लिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में भी गहन जांच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और घटना से जुड़ी हर संभव जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।

लगातार चौथे दिन राजौरी के मांजकोट में आतंकियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी

राजौरी, 26 मई । सुरक्षाबलों द्वारा चलाया जा रहा व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) मंगलवार को लगातार चौथे दिन भी राजौरी जिले के मांजकोट सेक्टर के घने जंगलों में गंभीर मुगलन और दोरिमाल में जारी रहा। यह अभियान क्षेत्र में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया गया है। यह संयुक्त अभियान भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा पीर पंजाल क्षेत्र के दुर्गम वन क्षेत्र में चलाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र में सुरक्षा तैनाती में काफी वृद्धि की गई है। स्थानीय निवासी आकिब खान ने कहा, संदिग्ध आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद से ही गंभीर मुगलन वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों की भारी मौजूदगी है। उन्होंने आगे कहा, फ्पूरे क्षेत्र को कड़ी घेराबंदी में रखा

गया है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। स्थानीय निवासी सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। एक अन्य निवासी मोहम्मद जावेद ने क्षेत्र के दुर्गम भूभाग की स्थिति पर प्रकाश डाला। बता दें कि इस क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच थोड़ी देर गोलीबारी हुई थी तभी से आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षाबलों द्वारा संयुक्त अभियान जारी है।

मुख्यमंत्री उमर ने 'राबिता' में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की

बैंकिंग, युवा विकास, विरासत संरक्षण और कला-संस्कृति को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा

श्रीनगर, मई 26। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज यहां अपने जन सेवा एवं जनसंपर्क कार्यालय 'राबिता' में कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की और बैंकिंग, युवा विकास, विरासत संरक्षण तथा जम्मू-कश्मीर में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जम्मू-कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताव चटर्जी ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय पहुंच और ग्राहक सेवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। एमडी एवं सीईओ ने मुख्यमंत्री को जम्मू-कश्मीर में बैंक की सेवाओं और कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने के प्रयासों की जानकारी दी, ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वात्स ने अतिरिक्त महानिदेशक एनसीसी निदेशालय जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख मेजर जनरल अनुपिंदर बेवली के साथ

मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने एनसीसी गतिविधियों, युवाओं की भागीदारी और जम्मू-कश्मीर में कैडेट पहलों के विस्तार से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटैक) के प्रतिनिधिमंडल ने, जिसके प्रमुख संयोजक और प्रमुख सलीम बेग तथा प्रधान वास्तुकार समीर हमदानी थे, मुख्यमंत्री को कश्मीर की विरासत संपत्तियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों पर पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला किया दर्ज

शोपियां, 26 मई। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के अवैध व्यापार की रोकथाम के तहत मामला दर्ज किया है।

आरोपियों की पहचान दारमदोरा कीगाम के हिलाल अहमद भट विश्राम पाईन के मोहम्मद यूसुफ भट और पुडसू शोपियां के परवेज अहमद थोकर के रूप में हुई है।

अधिकारियों ने कहा कि शोपियां पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए डोजियर के बाद कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर द्वारा हिरासत के आदेश जारी किए गए थे जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी में उनकी कथित बार-बार संलिप्तता और उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर का हवाला दिया गया था।

आरोपियों को क्रमश जम्मू की सेंट्रल जेल कोट भलवाल, जिला जेल राजौरी और जिला जेल पुंछ में रखा गया है।

पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवा कल्याण के लिए उनकी गतिविधियों से उत्पन्न गंभीर खतरा के कारण निवारक हिरासत प्राव

धानों के तहत कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दर्शाता है और जिले में मादक पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। शोपियां पुलिस ने कहा कि ड्रग तस्करों और उनके नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और जनता से संदिग्ध ड्रग गतिविधि से संबंधित जानकारी साझा करने का आग्रह किया।

बिलावर में एनडीपीएस आरोपी की 40 लाख की संपत्ति कुर्क

कठुआ/बिलावर, 26 मई । कठुआ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलावर क्षेत्र में एक एनडीपीएस आरोपी की करीब 40 लाख मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क किया है।

जानकारी के अनुसार यह संपत्ति दर्शन सिंह उर्फ दीपु निवासी गलक तहसील रामकोट की है जिसे पिट-एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया गया। जांच में सामने आया कि उक्त मकान नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से बनाया गया था। यह कार्रवाई एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के निर्देश पर की गई। मौके पर राजस्व विभाग की मौजूदगी में पुलिस टीम ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर संपत्ति को अटैच किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी के खिलाफ जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मामले पहले से दर्ज हैं।

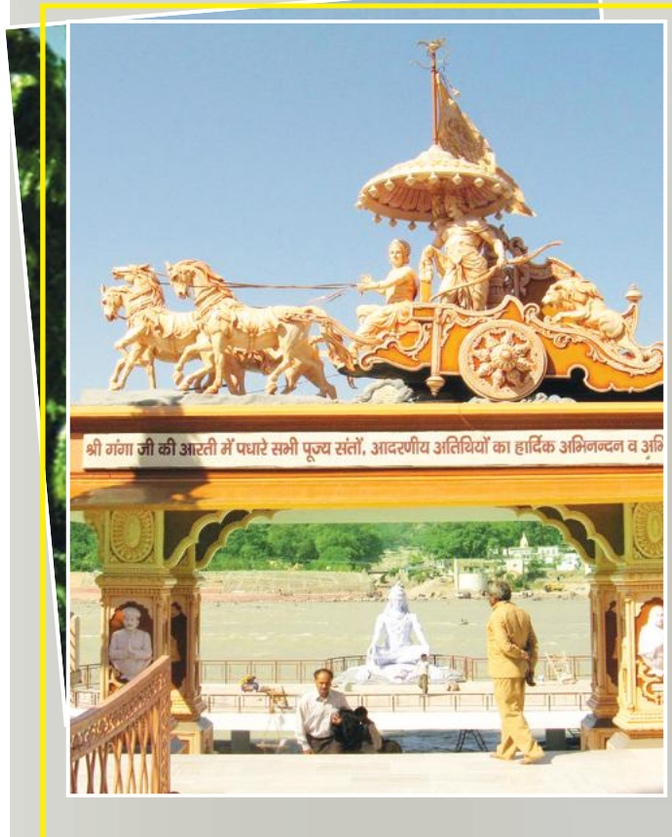

हिमालय का प्रवेशद्वार

ऋषिकेश

{ ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान यहां के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है। }

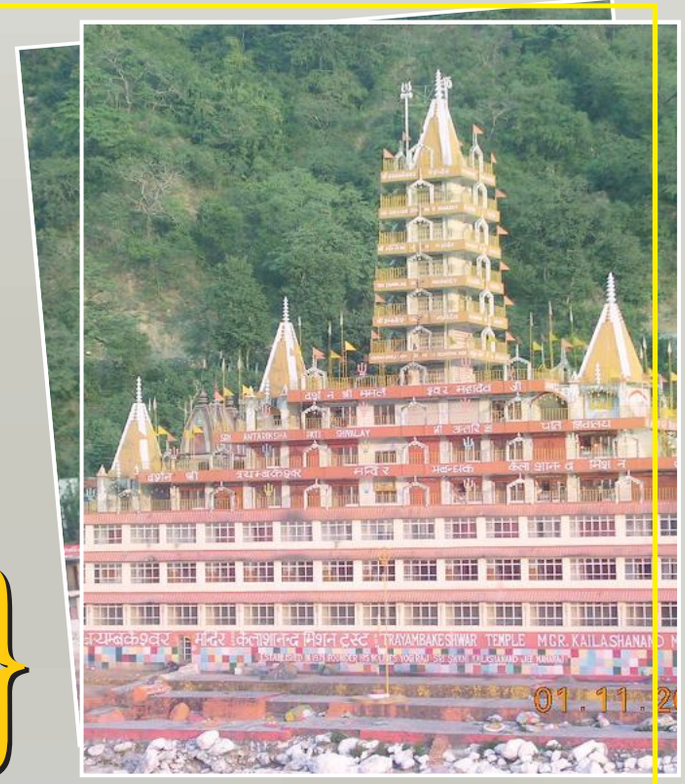

हिमालय का प्रवेश द्वार, ऋषिकेश जहां पहुंचकर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती है। हरिद्वार से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषिकेश विश्व प्रसिद्ध एक योग केंद्र है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। उत्तराखण्ड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में एक है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुन्दरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेशद्वार माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर साल यहां के आश्रमों के बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शान्ति के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहां आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं।

प्रचलित कथाएं

ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान यहां के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है। 1939 ई. में लक्ष्मण झूले का पुनर्निर्माण किया गया। यह भी कहा जाता है कि ऋषि राभ्या ने यहां ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के अवतार में प्रकट हुए। तब से इस स्थान को ऋषिकेश नाम से जाना जाता है।

लक्ष्मण झूला

गंगा नदी के एक किनार को दूसरे किनारे से जोड़ता यह झूला शहर की खास पहचान है। इसे 1939 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण ने इस स्थान पर जूट का झूला बनवाया था। झूले के बीच में पहुंचने पर वह हिलता हुआ प्रतीत होता है। 450 फीट लंबे इस झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ मंदिर हैं। झूले पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है। लक्ष्मण झूला के समान राम झूला भी नजदीक ही स्थित है। यह झूला शिवानंद और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है। इसलिए इसे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है।

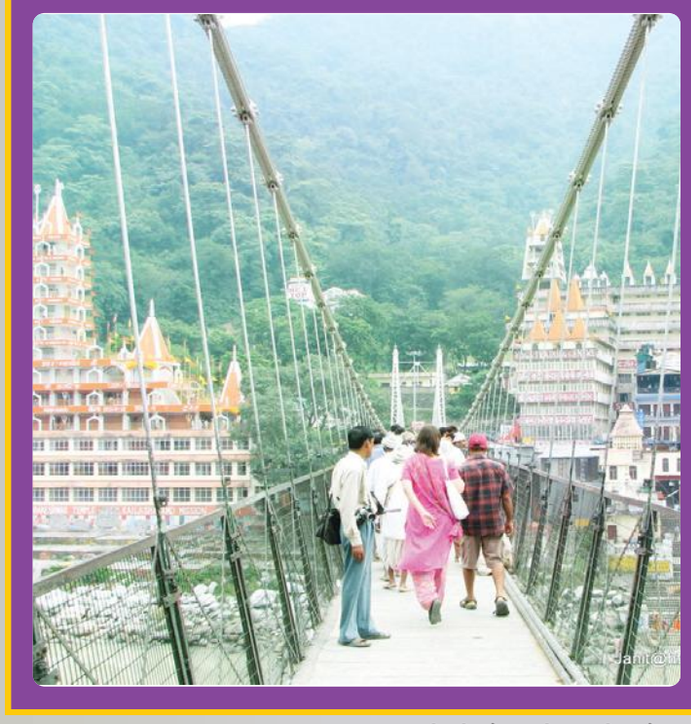

त्रिवेणी घाट

ऋषिकेश में स्नान करने का यह प्रमुख घाट है जहां प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिन्दु धर्म की तीन प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसी स्थान से गंगा नदी दायीं ओर मुड़ जाती है। शाम को होने वाली यहां की आरती का नजारा बेहद आकर्षक होता है।

राम झूला पुल

स्वामी विशुद्धानन्द द्वारा स्थापित यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्राचीन आश्रम है। स्वामी जी को काली कमली वाले नाम से भी जाना जाता था। इस स्थान पर बहुत से सुन्दर मंदिर बने हुए हैं। यहां खाने पीने के अनेक रेस्तरां हैं जहां सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। आश्रम की आसपास हस्तशिल्प के सामान की बहुत सी दुकानें हैं।

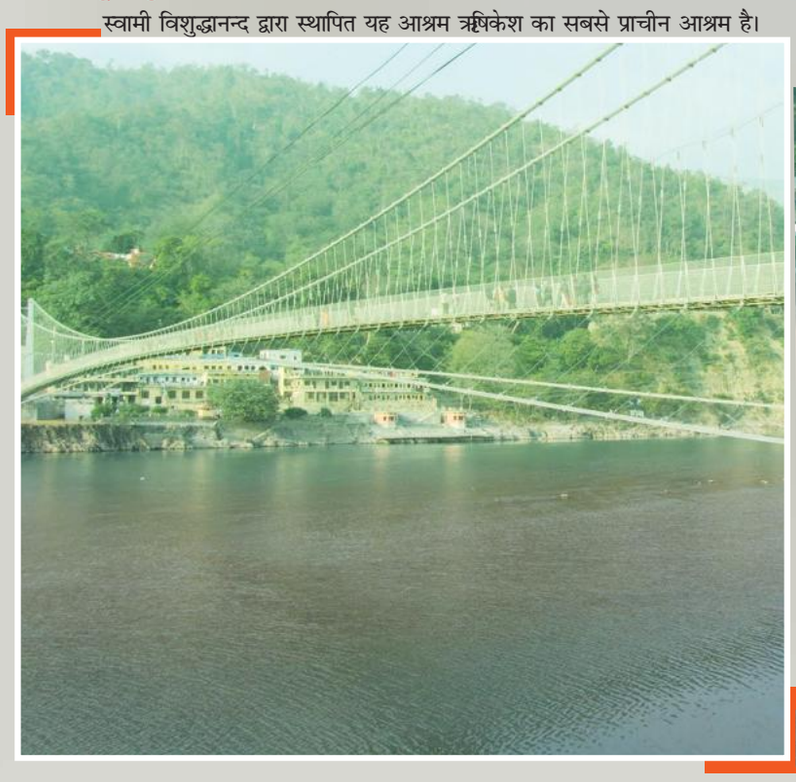

नीलकंठ महादेव मंदिर-

लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया गया था। विषपान के बाद विष के प्रभाव के से उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं।

भरत मंदिर-

यह ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है जिसे 12 शताब्दी में आदि गुरू शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट ओल्ड टाउन में स्थित है। मंदिर का मूल रूप 1398 में तैमूर आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हालांकि मंदिर की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को उस हमले के बाद आज तक संरक्षित रखा गया है। मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा एकल शालीग्राम पत्थर पर उकेरी गई है। आदि गुरू शंकराचार्य द्वारा रखा गया श्रीयंत्र भी यहां देखा जा सकता है।

कैलाश निकेतन मंदिर-

लक्ष्मण झूले को पार करते ही कैलाश निकेतन मंदिर है। 12 खंड़ों में बना यह विशाल मंदिर ऋषिकेश के अन्य मंदिरों से भिन्न है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं।

वशिष्ठ गुफा-

ऋषिकेश से 22 किमी. की दूरी पर 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा बद्रीनाथ-केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। इस स्थान पर बहुत से साधु विश्राम और ध्यान लगाए देखे जा सकते हैं। कहा जाता है यह स्थान भगवान राम और बहुत से राजाओं के पुरोहित वशिष्ठ का निवास स्थल था। वशिष्ठ गुफा में साधुओं को ध्यानमग्न मुद्रा में देखा जा सकता है। गुफा के भीतर एक शिवलिंग भी स्थापित है।

गीता भवन-

राम झूला पार करते ही गीता भवन है जिसे 1950 ई. में श्रीजयदयाल गोयन्काजी ने बनवाया गया था। यह अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। यहां रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षण बनाती हैं। यहां एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी और गीताप्रेस गोरखपुर की एक शाखा भी है। प्रवचन और कीर्तन मंदिर की नियमित क्रियाएं हैं। शाम को यहां भक्ति संगीत की आनंद लिया जा सकता है।

कैसे जाएं

वायुमार्ग-

ऋषिकेश से 18 किमी. की दूरी पर देहरादून के निकट जौली ग्रान्ट एयरपोर्ट नजदीकी एयरपोर्ट है। इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइटें इस एयरपोर्ट को दिल्ली से जोड़ती है।

रेलमार्ग-

ऋषिकेश का नजदीकी रलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो शहर से 5 किमी. दूर है। ऋषिकेश देश के प्रमुख रलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है।

सड़क मार्ग

दिल्ली के कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए डीलक्स और निजी बसों की व्यवस्था है। राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से दिल्ली और उत्तराखंड के अनेक शहरों से ऋषिकेश के लिए चलती हैं।

तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए यहां सैकड़ों कमरे हैं।

खरीददारी

ऋषिकेश में हस्तशिल्प का सामान अनेक छोटी दुकानों से खरीदा जा सकता है। यहां अनेक दुकानें हैं जहां से साड़ियों, बेड कवर, हैन्डलूम फेबरिक, कॉटन फेबरिक आदि की खरीददारी की जा सकती है। ऋषिकेश में सरकारी मान्यता प्राप्त हैन्डलूम शॉप, खादी भंडार, गढ़वाल वूल और क्राफ्ट की बहुत सी दुकानें हैं जहां से उच्चकोटि का सामान खरीदा जा सकता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

याशा मुद्गल ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अनंतनाग के प्रदर्शन की समीक्षा की

जम्मू, मई 26। सहकारिता विभाग की आयुक्त सचिव याशा मुद्गल ने आज द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यूसीबी) अनंतनाग की परिचालन कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहकारिता विभाग के वित्तीय सलाहकार, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक अनंतनाग के जीएम/सीईओ, सहायक पंजीयक (मुख्यालय) सहकारी समितियां जम्मू-कश्मीर, यूसीबी अनंतनाग के सभी शाखा प्रमुख तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक अनंतनाग के जीएम/सीईओ ने बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। समीक्षा में जमा राशि, ऋण वितरण, रिकवरी प्रदर्शन, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए), कुल लाभ, कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेशियो (सीआरएआर), शाखा-वार प्रदर्शन तथा डिजिटल बैंकिंग और तकनीकी उन्नयन की प्रगति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। आयुक्त सचिव को बताया गया कि बैंक ने स्थापना से अब तक लगातार ए ग्रेड ऑडिट वर्गीकरण बनाए रखा है और इसकी सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह संचालित हो रही हैं। इसके अलावा बैंक ने उन्नत डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई, स्पॉन्सर बैंक और विक्रेता एजेंसियों के साथ आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने, अनिवार्य वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग (वीएपीटी), सूचना सुरक्षा ऑडिट और ईडीपी ऑडिट जैसे कदम भी शुरू किए हैं, जो आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। वित्तीय संकेतकों की समीक्षा करते हुए याशा मुद्गल ने बैंक प्रबंधन को एनपीए पर नियंत्रण के लिए आक्रामक रिकवरी तंत्र अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रॉस एनपीए अनुपात किसी भी स्थिति में बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए और लगातार निगरानी, नियमित रिकवरी फॉलो-अप तथा विवेकपूर्ण ऋण नीति के जरिए नए एनपीए बनने से रोकने के निर्देश दिए।

विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, डीसी कठुआ ने की प्रगति की समीक्षा

कठुआ, 26 मई (हि.स.)। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने मंगलवार को जिला कैपेक्स बजट 2026-27, विधायक निधि और सांसद निधि के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की।

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जेपीडीसीएल सहित विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों का जायजा लिया गया।

साथ ही डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई ग्रांट्स के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति भी परखी गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के

साथ पूरे किए जाएं ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके। उन्होंने ठेकेदारों के कार्यों की नियमित निगरानी और मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि एमएलए-सीडीएफ के तहत 748 कार्यों को मंजूरी मिली है जिनमें से 727 टेंडर, 713 आवंटित और 699 कार्य शुरू हो चुके हैं जबकि 542 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं एमपी लैड के तहत भी अधिकांश कार्यों में संतोषजनक प्रगति दर्ज की गई है। बैठक में एडीसी महिमा मदान, सीपीओ रणजीत ठाकुर, एसीडी अखिल सदोत्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

वेदों के ज्ञान से दूर हों भ्रम, विद्वानों से प्रश्न करना आवश्यक : स्वामी राम स्वरूप जी

कठुआ, 26 मई (हि.स.)। वेद मन्दिर योल में चल रहे 78 दिवसीय चारों वेदों के यज्ञानुष्ठान के 45वें दिन स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य ने जिज्ञासुओं एवं आमजन को वेदों के अनुसार जीवन जीने का मार्ग बताया।

उन्होंने कहा कि ईश्वर, प्रकृति और जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए मनुष्य को वेदों के ज्ञाता, इन्द्रिय संयमी एवं तपस्वी विद्वानों के सानिध्य में रहकर प्रश्न करना चाहिए। विद्वान वेदों के अनुसार उत्तर देकर अज्ञान और भ्रम को दूर करते हैं तथा ज्ञान का प्रकाश करते हैं।

स्वामी जी ने यजुर्वेद मंत्र 23/9 का उदाहरण देते हुए बताया कि वेदों में प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने की विधि स्पष्ट की गई है। उन्होंने बताया कि सूर्य अकेला चलता है, चन्द्रमा पुनः उत्पन्न होता है, अग्नि ठंड की औषधि है और भूमि बीज बोने का श्रेष्ठ क्षेत्र है। उन्होंने वर्षा को प्रथम स्मृति का विषय बताते हुए कहा कि अन्न और जीवन का आधार वर्षा ही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में प्रश्नोत्तर की परंपरा भी वेदों से ही प्रेरित है। यदि जिज्ञासु प्रश्न नहीं करेगा तो वह अज्ञानी ही रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर न दे सके, वह सच्चा विद्वान नहीं कहलाता।

डीजीपी ने कश्मीर घाटी की मस्जिदों में व्यापक सुरक्षा और गश्त तेज करने के दिए निर्देश

श्रीनगर, 26 मई (हि.स.)। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने कश्मीर घाटी की मस्जिदों और प्रमुख सामूहिक प्रार्थना स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, सार्वजनिक आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त कर्मियों की तैनाती की आवश्यकता पर बल दिया।

कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को ईद-उल-अधा और श्री अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई। उन्होंने फील्ड अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक निरीक्षण करने और गश्त तेज करने का निर्देश दिया ताकि त्योहार के दौरान किसी भी संभावित सुरक्षा, चिंता का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने प्रस्तावित सुरक्षा और रसद व्यवस्थाओं के साथ-साथ तैयारियों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

सीएपीएफ व अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने भी अपने आकलन साझा किए और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय और तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने अध्यक्ष को आने वाली सीएपीएफ कंपनियों के लिए की गई प्रशासनिक और रसद व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी।

डीजीपी ने सीएपीएफ कंपनियों के सुचारू रूप से शामिल होने के निर्देश जारी किए और इस बात पर जोर दिया कि जिला प्रमुखों को आने वाली इकाइयों के लिए उचित व्यवस्था और उनकी कुशल जमीनी तैनाती सुनिश्चित करनी चाहिए।

ट्रैफिक पुलिस पुंछ ने एक स्टंट बाइक सवार के खिलाफ की कार्रवाई

पुंछ, 26 मई (हि.स.)। पुंछ के मेंढर पुल के पास खतरनाक बाइक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस पुंछ ने एक स्टंट बाइक सवार के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी की पहचान मेंढर के अरी निवासी तौफीक हयात के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ खतरनाक ड्राइविंग, बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट बाइक चलाने के आरोप में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही संबंधित मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है।

एस.एस.पी. ट्रैफिक ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए इस तरह के जानलेवा स्टंट न करें, क्योंकि इससे न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में पड़ती है और यह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी है।

तकनीकी खराबी के चलते गुलमर्ग गोंडोला करीब एक हफ्ते तक बंद रहेगा

श्रीनगर, 26 मई (हि.स.)। गुलमर्ग गोंडोला सेवा में तकनीकी खराबी के बाद कश्मीर पर्यटन निदेशक सैयद कमर सज्जाद जो जम्मू-कश्मीर केबल कार निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते हैं ने मंगलवार को कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोंडोला परिचालन करीब एक हफ्ते तक निलंबित रहेगा। उन्होंने बताया कि कोंडोरी स्टेशन (जिसे आमतौर पर फजी2फ कहा जाता है) के प्राथमिक गियरबॉक्स में तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण अधिकारियों को परिचालन निलंबित करना पड़ा और फंसे हुए पर्यटकों को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि हमें खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गोंडोला लगभग एक सप्ताह तक बंद रहेगा। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद संचालन पुनः शुरू हो जाएगा। सुरक्षा और संरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खराबी सामने आने के बाद अधिकारियों के पास दो विकल्प थे - या तो खराब गियरबॉक्स की मरम्मत करना या बीच में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए आपातकालीन ऊर्ध्वाधर बचाव अभियान चलाना। उन्होंने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद हमारी प्राथमिकता पर्यटकों के जीवन की रक्षा करना थी। हमने ऊर्ध्वाधर बचाव प्रणाली के माध्यम से तुरंत बचाव अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि छह विशेष बचाव दल गठित किए गए और गोंडोला लाइन के ऊपर, मध्य और नीचे के हिस्सों में तैनात किए गए। उन्होंने कहा कि यह अभियान जम्मू-कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के समन्वय से चलाया गया। उन्होंने कहा कि सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और वे गुलमर्ग में अपने प्रवास का आनंद ले रहे हैं।

बसोहली में ईद-उल-अजहा की तैयारियां तेज, स्वच्छता से लेकर सुरक्षा तक प्लान तैयार

बसोहली, 26 मई (हि.स.)। ईद-उल-अजहा के अवसर पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए एडीसी बसोहली पंकज भगोत्रा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप-जिला स्तर पर त्योहार की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में तहसीलदार बसोहली सागर विश्वकर्मा, नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार सहित स्वास्थ्य, जल शक्ति, बिजली, खाद्य एवं आपूर्ति, ग्रामीण विकास और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। एडीसी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से ईदगाहों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास साफ-सफाई और कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जल शक्ति विभाग को सभी धार्मिक स्थलों पर निर्बाध पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए

26 और 27 मई को जम्मू और कश्मीर में आमतौर पर गर्म और शुष्क मौसम रहने की संभावना

श्रीनगर, 26 मई (हि.स.)। श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 और 27 मई को जम्मू और कश्मीर में आमतौर पर गर्म और शुष्क मौसम की संभावना व्यक्त की है जिसमें 27 मई की दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 29 मई तक मौसम आमतौर पर बादल छाए रहने वाला रहेगा साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के छिटपुट से लेकर व्यापक स्थानों पर एक या दो बार बारिश, गरज के साथ बौछारें, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने कहा कि 30 मई से 3 जून तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि दोपहर के समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्वानुमान में आगे कहा गया है कि 4 जून को आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है साथ ही दोपहर के समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है जबकि 5 से 7 जून तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD(R&B) DIVISION VIJAYPUR

ABBREVIATED NOTICE INVITING TENDER

e-NIT No. 14 of 2026-27 Dated. 25-05-2026

For and on behalf of the Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir e-tenders are invited on percentage basis from approved and eligible Contractors registered with Union Territory of J&K, CPWD, Railways, MES and other State/Central Governments for each of the following works

S.No.	Name of Work	Estimated cost of Work (in Lacs)	Cost of Tender Doc. (in Rs.)	Earnest Money (In Rs.)	Time allowed for completion	Class of Contractor
1	2	3	4	5	6	7
1	Facelifting and renovation work at lodgement centres viz Radha Swami Satsang Ghar Najwal, Rameshwar Dham Mandir Tarore, Sita Ram Mandir beas 17 Miles, Sahib Bandhgi Ashram Ranjri and Baba Sidh Goria Ashram. (2nd Call)	3.00	600	2% of Adv. Cost	15 Days	"A, B, C & D"

Position of AAA :- Accorded
Position of T.S :- Sanctioned
Project Authority :- Under REVEX Budget on account of Shri Amarnath Ji Yatra 2026.

1	Date of Issue of Tender Notice	25-05-2026
2	Period of downloading of bidding documents	From 25-05-2026 to 30-05-2026
3	Date, Time and place of pre-bid meeting	26-05-2026 at 1400 Hrs. in the Office of Executive Engineer PWD (R&B) Division Vijaypur.
4	Bid submission Start Date	25-05-2026 at 1800 Hrs
5	Bid Submission End Date	30-05-2026 upto 1800 Hrs
6	Date & time of opening of Technical Bids (Online)	01-06-2026 on or after 1400 Hrs in the Office of Executive Engineer PWD (R&B) Division Vijaypur.
7	Date & time of opening of Financial Bids (Online)	To be notified after technical bid evaluation is completed.

The tender is available at website http://jktenders.gov.in all other terms & conditions can be seen on the above website.

No. PWD/V/1331-37
Dt. 25-05-2026

DIP/J-2742/26
Dtd: 26-5-2026

Sd/-
Executive Engineer,
PWD (R&B) Division,
Vijaypur

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, JAL SHAKTI (PHE) DIVISION UDHAMPUR NOTICE INVITING TENDER

e-NIT No. 11 OF 2026-27 DATED 22-05-2026
UNDER ENDORSEMENT NO. JSDU/ 1466-94 DATED:-22-05-2026

For and on behalf of Lt. Governor of UT of Jammu & Kashmir, Executive Engineer, Jal Shakti (PHE) Division, Udhampur invite tenders by e-tendering mode on Item wise rates from the registered Firms / suppliers for supply of material as under in accordance with the terms and conditions specifications described in the BOQ.

S. No.	Name of work	Name of Division	Cost of document/ tender fee (In Rs.)	Earnest Money (in Rs.) to be uploaded online	Performance Security (in Rs.) to be submitted by the successful bidder
1	2	3	4	5	6
1	Supply of Led Pig and Spun Yarn as per BOQ	Jal Shakti PHE Division Udhampur	500.00	10000.00	20000.00

1. Date of Publishing 22-05-2026
2. Bid documents can be seen at and downloaded from the website http://jktenders.gov.in from 22-05-2026 from 1800 (Hrs)
3. The Bids shall be deposited on the website http://jktenders.gov.in from 22-05-2026 (18:00 Hrs) to 05-06-2026 (1600 Hrs).
4. The complete bidding process will be online.
5. The Technical bids received shall be opened online on 06-06-2026 (1400 Hrs) in the office of Executive Engineer Jal Shakti PHE Division Udhampur.
6. The Financial bids of the bidders shall be opened online in the office of the Executive Engineer Jal Shakti PHE Division Udhampur and shall be communicated separately.
7. Bids must be accompanied by cost of Tender Document and bid security as specified in column 4 of the table payable at Udhampur pledged in favour of Executive Engineer, Jal Shakti PHE Division Udhampur. The cost of downloaded tender documents in the form of E-Challan, Treasury challan /Receipt under MH-0215 - WSS (Revenue Head) shall be in separate envelop with cover marking cost document pledged in favour of Executive Engineer, Jal Shakti PHE Division Udhampur mentioning the e-NIT No. / S. No of the work OR Tender fee can be submitted through NEFT / RTGS in J&K Bank Branch Udhampur bearing Bank Account No. 0028010200000047, IFSC code JAKAOUDMPUR in favour of Executive Engineer Jal Shakti (PHE) Division Udhampur, mentioning the e-NIT No. / Name of the work.
8. As per the instruction of the principal secretary to Government Finance Department J&K Srinagar vide his No. O.M.No. A/24 (2017)-61 dated 07.06.2018 regarding furnishing of hard copies of bids immediately after submission of e-tenders is dispensed with. The same should be obtained only from the bidder who is declared as L1 after opening of financial bid. The cost of tenders should be collected by introducing e-challan or simply uploading a copy of necessary treasury challan / receipt.
9. EMD of Rs. 10000/- shall be released on receipt of performance security of Rs. 0.20 lacs from the successful bidder.
10. The bid shall remain open for acceptance for a period of 30 days from the date of opening of bids.
11. Other details can be seen in the bidding documents.
12. The bidder shall have to quote rates for each item otherwise, the bid shall be treated as non-responsive and shall be rejected even after opening of financial bid. Partially / selected quoted rates shall not accepted.

Instruction to bidders regarding e-tendering process:-

. The interested bidder can download the NIT/bidding document from the website http://jktenders.gov.in
b. To participate in bidding process, bidders have to get (DSC) "Digital Signature Certificate" as per Information Technology Act-2000, to participate in online bidding. This certificate will be required for digitally signing the bid. Bidders can get above mentioned digital certificate from any approved vendors. The Bidders, who already possess valid (DSC) Digital Signature Certificates, need not to procure new Digital Signature Certificate.
c. The bidders have to submit their bids online in electronic format with Digital Signature. The bids cannot be uploaded without Digital Signature. No Proposal will be accepted in physical form.
d. Bids will be opened online as per time schedule.
e. Before submission of online bids, bidders must ensure that scanned copies of all the necessary documents have been attached with bid.
f. The department will not be responsible for delay in online submission of bids whatsoever reasons may be.
g. All the required information for bid must be filled and submitted online
h. Bidders should get ready with the scanned copies of cost of documents as specified in the tender documents. The original documents in respect of cost of documents and relevant documents shall have to be submitted by the L1 within 3days after opening of Financial bid in the office of the [Executive Engineer Jal Shakti PHE Division Udhampur] during office working hrs.
i. The details of cost of documents specified in the tender documents should be the same, as submitted online (scanned copies) otherwise bid will not be accepted.
j. Bidders can contact the undersigned for any guidance for getting DSC or any other relevant details in respect of e-tendering process.
k) Bidders are advised to use "My Documents" area in their user on jktenders.gov.in, e-tendering portal to store important documents like GST, IT certificate, etc., and attach these certificates as Non Statutory documents while submitting their bids.
l) Bidders are advised not to make any change in BOQ (Bill of Quantities) contents or its name. In no case they should attempt to create similar BOQ manually. The BOQ downloaded should be used for filling the above / below rate inclusive of all taxes and it should be saved with the same as it contains.
m) Bidders are advised to scan their documents at 100 DPI (Dots per Inch) resolutions with Black and White, JPEG Scan properly, convert scanned images to PDF
n) The guidelines for submission of bid online can be downloaded from the website http://jktenders.gov.in

DIP/J-2722/26
Dtd: 26-5-2026

Sd/-
Executive Engineer
Jal Shakti PHE Division
Udhampur

कठुआ पुलिस की तत्परता-लापता युवती 13 दिन बाद सकुशल परिजनों से मिली

कठुआ, 26 मई (हि.स.)। कठुआ पुलिस ने चडवाल क्षेत्र में एक लापता युवती को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के साथ मिला दिया। जानकारी के अनुसार बीते 12 मई 2026 को हीरानगर तहसील के छपाकी निवासी जगन नाथ ने अपनी 22 वर्षीय बेटी रेनू देवी के लापता होने की शिकायत पुलिस पोस्ट चडवाल में दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के निर्देशन में पुलिस पोस्ट चडवाल की टीम ने तकनीकी सहायता और मानवीय प्रयासों के जरिए युवती को ढूंढ निकाला। पुलिस ने 25 मई को युवती को बरामद कर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे उसके परिजनों को सौंप दिया।

इंडिगो विमान में धुआं दिखने से मची अफरा-तफरी, आपात निकासी के दौरान दो यात्री घायल

बेंगलुरु, 26 मई (हि.स.)। बेंगलुरु से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक उड़ान में केबिन और कॉकपिट में धुआं दिखाई देने के बाद यात्रियों को आपात स्थिति में विमान से बाहर निकाला गया। घटना के दौरान सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, हालांकि निकासी प्रक्रिया के दौरान दो यात्रियों को मामूली चोटें आईं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, इंडिगो का एयरबस ए321 विमान उड़ान संख्या 6ई-6017 बेंगलुरु से चेन्नई के लिए रवाना होने वाला था। विमान के पुशबैक के बाद टैक्सी प्रक्रिया शुरू होने के दौरान कॉकपिट और केबिन में धुआं देखा गया, जिसके बाद चालक दल ने तत्काल आपात प्रोटोकॉल लागू किया।

स्थिति को देखते हुए चालक दल ने सभी इमरजेंसी स्लाइड का इस्तेमाल करते हुए यात्रियों की सुरक्षित निकासी कराई। इस दौरान अफरा-तफरी के बीच दो यात्रियों को हल्की चोटें आईं। अधिकारियों के अनुसार दोनों की स्थिति सामान्य बताई गई है।

घटना के बाद संबंधित विमान को जांच और तकनीकी सुधार के लिए फिलहाल सेवा से हटा दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विमानन नियामक संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

संपादकीय

लापरवाही से टल गई बड़ी त्रासदी

गुलमर्ग गोंडोला में सोमवार को लगभग 320 पर्यटकों के हवा में फंस जाने की भयावह घटना केवल एक तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही और कश्मीर के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में सुरक्षा प्रबंधन की कमजोर स्थिति का बड़ा संकेत थी। हालांकि सफल रेस्क्यू ऑपरेशन ने एक बड़ी त्रासदी टाल दी, लेकिन इस घटना ने गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है, जिनके लिए सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती।

कई घंटों तक महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पर्यटक सैकड़ों फीट ऊंचाई पर हवा में लटके रहे, जब दोपहर करीब 1 20 बजे तकनीकी खराबी के कारण केबल कार सेवा रुक गई। मौसम खराब होने और अनिश्चितता बढ़ने के साथ केबिनों में दहशत फैल गई। यदि स्थिति और बिगड़ जाती, तो घाटी हाल के वर्षों की सबसे बड़ी पर्यटन त्रासदियों में से एक की गवाह बन सकती थी।

सरकार अब रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर सकती है, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इतनी खतरनाक स्थिति पैदा ही क्यों होने दी गई? गुलमर्ग गोंडोला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर पर्यटन के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया जाता है और हर सीजन हजारों पर्यटक यहां आते हैं। यदि इतनी महत्वपूर्ण परियोजना में इतनी बड़ी तकनीकी विफलता हो सकती है, तो जम्मू-कश्मीर की अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं में सुरक्षा निगरानी और रखरखाव की स्थिति पर गंभीर सवाल उठते हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा दिखाए गए साहस और पेशेवर रवैये की सराहना की जानी चाहिए। उनकी त्वरित कार्रवाई ने लोगों की जान बचाई और स्थिति को बड़े हादसे में बदलने से रोका। लेकिन बचाव कर्मियों की बहादुरी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने का माध्यम नहीं बननी चाहिए।

रिपोर्टों के अनुसार लगभग 45 शारीरिक रूप से अस्वस्थ पर्यटकों को खराब मौसम और कठिन रास्तों के बीच स्ट्रेचर के सहारे नीचे लाया गया। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि गोंडोला प्रणाली के भीतर प्रभावी आपातकालीन निकासी व्यवस्था क्यों मौजूद नहीं थी। जिस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर हो, वहां ऐसे संकट में केवल मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन पर निर्भर रहना कमजोर तैयारी और पुरानी सुरक्षा योजना को दर्शाता है।

पर्यटन केवल प्रचार अभियानों के सहारे नहीं चल सकता। सरकार लगातार कश्मीर को सुरक्षित और विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बताती रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच खतरनाक अंतर को उजागर करती हैं। जनता यह जानना चाहती है कि रखरखाव शेड्यूल, सुरक्षा ऑडिट, तकनीकी निरीक्षण और इस विफलता की जवाबदेही किसकी है।

यह केवल एक टला हुआ हादसा नहीं था, बल्कि एक गंभीर चेतावनी थी। जम्मू-कश्मीर के लोगों और देशभर से आने वाले पर्यटकों को ऐसी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो प्रशासनिक लापरवाही से ऊपर मानव जीवन को प्राथमिकता दें। यदि अब भी सबक नहीं लिया गया, तो अगली घटना राहत और शुक्रगुजारी के बजाय शोक और पछतावे में बदल सकती है।

एआई का जनजातीय भाषाओं में संवाद: समावेशी विकास का द्योतक

भगवान बिरसा मुंडा सेल और आईआईटी दिल्ली के साथ आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान भी इन प्रयासों पर चर्चा की गई, जो जनजातीय भाषाओं के दीर्घकालिक संरक्षण और सुदृढ़ीकरण सहित एआई के सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और समुदाय-केंद्रित इस्तेमाल पर केंद्रित थी। प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक अभिकथन और आर्थिक सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन रही है। आगामी ट्राइबएक्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जनजातीय कलाओं, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान, संगीत, शिल्प और सांस्कृतिक अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है।

श्रीमती रंजना चोपड़ा

हमारे देश भर में फैले जंगलों, पहाड़ियों और दूरदराज की बस्तियों में, एक शांत लेकिन सफल परिवर्तन चल रहा है। जनजातीय समुदाय लंबे समय से भारत की विकास गाथा के केंद्र में अपने उचित स्थान का इंतजार कर रहे थे। आज वे राष्ट्र की प्रगति के सक्रिय वास्तुकार के रूप में उभर रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव की यही भावना है- विकसित भारत की यात्रा का एक राष्ट्रीय उत्सव, जहां प्रगति भूगोल या परिस्थिति का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का समान रूप से अधिकार है। महत्वाकांक्षा का पैमाना यह समझने के लिए कि प्रौद्योगिकी जनजातीय विकास के लिए अपरिहार्य क्यों हो गई है, किसी को पहले चुनौती की व्यापकता को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और संबंधित पहलों में 549 जिलों और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,911 ब्लॉकों के 63,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 5.5 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिक लाभान्वित हुए हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) पर विशेष ध्यान देने के साथ, इन प्रयासों का उद्देश्य आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसी आवश्यक सेवाओं का सम्पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। इस तरह के विविध और विस्तृत इलाके में हर परिवार तक पहुंचने के लिए ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जो डेटा- संचालित, कनेक्टेड और उत्तरदायी होती है और यही हम तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष जनजातीय गरिमा उत्सव का आयोजन लगभग चार विषयगत सप्ताह के आसपास किया जा रहा है, जो एक साथ जनजातीय विकास के पूर्ण आयाम को दर्शाते हैं। उद्घाटन का विषय, विकास के एक वाहक के रूप में प्रौद्योगिकी इस बात को दर्शाता है कि कैसे डिजिटल सिस्टम, विज्ञान और नवाचार भारत के कुछ दूरस्थ समुदायों तक शासन और अवसर का विस्तार करने में मदद कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण के केंद्र में एक सरल सिद्धांत निहित है- जनजातीय भाषाओं, संस्कृतियों, विरासत और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का पर्याप्त सम्मान करते हुए विकास को अंतिम दूरी तक पहुंचना चाहिए। प्रौद्योगिकी द्वारा जनजातीय गरिमा को बढ़ावा उद्देश्य के साथ निर्देशित होने पर प्रौद्योगिकी क्या हासिल कर सकती है, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बिरसा 101 यानी सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी सीआरआईएसपीआर-आधारित जीन थेरेपी है। सिकल सेल रोग लंबे समय से जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य की एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है और भारत अब समानता और पहुंच में निहित उन्नत विज्ञान के साथ उस चुनौती का जवाब दे रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफजीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अनुसंधान, नैदानिक परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। सीएसआईआर-आईजीआईबी में हाल ही में एक संगोष्ठी में वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और सिकल सेल योद्धाओं को एक साथ लाया गया, जो वैज्ञानिक प्रगति और प्रयासों के पीछे की मानवीय तात्कालिकता दोनों को दर्शाता है। साझा लक्ष्य स्पष्ट है- एक किफायती, एकमुश्त उपचारात्मक उपचार विकसित करना जो जरूरतमंद हर आदिवासी परिवार तक पहुंच सके। बीआईआरएसए 101 केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि से भी बढ़कर है। यह एक घोषणा है कि भारत का सबसे उन्नत विज्ञान अपने सबसे पात्र समुदायों की सेवा करेगा। यह दृढ़ विश्वास एक पहल से कहीं अधिक गहरा है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) और आयुर्जेनोमिक्स जैसे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक आदिवासी समुदायों द्वारा लंबे समय से संरक्षित समृद्ध औषधीय और पारिस्थितिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण, मान्यीकरण और संरक्षण में मदद कर सकती है। समावेशन की यही भावना इस बात को आकार दे रही है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जनजातीय विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में, मंत्रालय ने एक सरल लेकिन दृढ विश्वास पर आधारित एआई-सक्षम प्लेटफार्मों की श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भाषा एक बाधा नहीं है जिसे दूर किया जाना है, बल्कि एक पहचान है जिसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। आदि वाणी, जनजातीय भाषाओं के लिए एआई-संचालित अनुवादक, टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-स्पीच अनुवाद, ओसीआर और आदिवासी भाषाओं में सरकारी योजना की जानकारी के वितरण का समर्थन करता है, जिससे नागरिकों को घर पर बोलने वाली भाषा में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ने में सक्षम बनाया जाता है। ट्राइबॉट एक बहुभाषी संवादी एआई सहायक है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को तत्क्षण मार्गदर्शन और शिकायत निपटारे में सहायता प्रदान करके इस प्रयास को और मजबूत करता है।

भगवान बिरसा मुंडा सेल और आईआईटी दिल्ली के साथ आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान भी इन प्रयासों पर चर्चा की गई, जो जनजातीय भाषाओं के दीर्घकालिक संरक्षण और सुदृढ़ीकरण सहित एआई के सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और समुदाय-केंद्रित इस्तेमाल पर केंद्रित थी। प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक अभिकथन और आर्थिक सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन रही है। आगामी ट्राइबएक्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जनजातीय कलाओं, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान, संगीत, शिल्प और सांस्कृतिक अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। इस प्रयास को पूरा करते हुए, जनजातीय भारत का प्रस्तावित जीआई संभावित कला और शिल्प एटलस भौगोलिक संकेत क्षमता के साथ जनजातीय हस्तशिल्प, वन उत्पादों और पारंपरिक कला रूपों का डिजिटल रूप से मानचित्रण करेगा, जिससे ब्रांडिंग, बाजार पहुंच और जनजातीय बौद्धिक विरासत की पहचान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पायलट आधार पर पांच राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में इनोवेशन हब की योजना बनाई गई है, जो नवाचार के नेतृत्व वाले आदिवासी उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए डिजाइन और उत्पाद विकास सहायता, जीआईएस-आधारित योजना डैशबोर्ड और इनक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर और आगे बढ़ेंगे। प्रौद्योगिकी जनजातीय समुदायों तक शासन के तरीके को समान रूप से बदल रही है। पीवीटीजी घरेलू सर्वेक्षणों के लिए पीएम-जनमन के तहत सर्वेक्षण सेतु दूरदराज के क्षेत्रों में कल्याण वितरण की तत्क्षण, जियो-टैग निगरानी को सक्षम बनाता है। 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में संचालित, इस प्लेटफॉर्म ने 8,552 सर्वेक्षणकर्ताओं के समर्थन के साथ पहले ही 3.43 लाख घरेलू प्रस्तुतियां दर्ज की हैं। इस तरह की डेटा-संचालित प्रणालियां यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि प्रत्येक पात्र परिवार की पहचान की जाए और उसे आवश्यक सेवाओं से जोड़ा जाए। इसके साथ ही मंत्रालय दावा प्रस्तुतीकरण, जीआईएस-आधारित मानचित्रण, वर्कफ्लो की निगरानी और शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एआई-सक्षम वन अधिकार अधिनियम शासन मंच विकसित कर रहा है। साथ में, ये पहल आदिवासी नागरिकों के लिए शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और सुलभ बना रही हैं। जनजातीय समुदाय-विकसित भारत के वाहक एक क्षण ऐसा होता है, जो उस सार को पकड़ लेता है, जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। यह किसी नीतिगत दस्तावेज या मंत्रिस्तरीय समीक्षा में नहीं पाया जाता है। यह तब पाया जाता है जब दूरदराज की बस्ती की एक आदिवासी महिला, तकनीक से, भाषा से सशक्त होती है और उसे इस बात का अहसास होता हो कि उसकी बात को राष्ट्र सुन रहा है। ऐसे में वह अपनी शर्तों पर सरकारी सेवाओं से जुड़ती है और पूरी गरिमा के साथ जवाब प्राप्त करती है। वह क्षण किसी यात्रा का अंत नहीं है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा में एक नए अध्याय की शुरुआत है। जनजातीय गरिमा उत्सव इस संदेश को गर्व के साथ ले जाता है। जनजातीय समुदाय, अपनी दृढता, अपने पारिस्थितिक ज्ञान, अपनी कलात्मक परंपराओं और इस भूमि में अपनी गहरी जड़ों के साथ, विकसित भारत की दहलीज पर इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इसके सबसे

शक्तिशाली और प्रेरक वाहकों में शामिल हैं। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी दूरियों को पाटती है, जैसे-जैसे विज्ञान उपचार प्रदान करता है, जैसा कि एआई जंगलों और पहाड़ियों की भाषाओं में बोलता है, और जैसे-जैसे शासन सबसे दूर के गांव के अंतिम परिवार तक पहुंचता है, हम हर दिन भारत के करीब आते हैं जो न केवल व्यापकता के रूप में विकसित है, बल्कि अपनी मानवता मेंपरिपूर्ण है। यह वह विकसित भारत है जिसे हम माननीय प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकरएक साथ मिलकर निर्मित कर रहे हैं।

(लेखिका भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव हैं)

सूरज के तीखे होते तेवर और अल-नीनो

प्रमोद भार्गव

देश के ज्यादातर भूभाग पर पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र समेत समूचा मध्य व उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। 25 मई को सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नौतपा शुरू हो जाएंगे, तब अनुमान है कि पहले ही तप रही धरती आसमान से बरसाने वाली इस आग से और अधिक गर्म हो जाएगी। हालांकि भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार धरती का अधिक तपना अच्छी बारिश का संकेत है। मौसम विभाग भी नौतपा में भीषण गर्मी बता रहा है। सनातन पंचांग में उल्लेख मिलता है कि इन नौ दिनों में एक ऐसा समय भी आता है जब सूर्य अपनी सबसे तीव्र ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर प्रभाव डालता है। फलत: गर्मी चरम पर पहुंच जाती है।

इस परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकों की मानें तो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में एक ताकतवर महा-अल नीनो आकार ले रहा है। यह 1877 के बाद सबसे विध्वंसकारी मौसमी आपदा साबित हो सकता है। इसका सीधा असर भारत में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अल-नीनो भारत की जीवन रेखा कहे जाने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून को भी प्रभावित कर सकता है। मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काई मेट के अनुसार इसका मुख्य कारण केवल सामान्य मौसमी बदलाव न होकर ऊष्मा का बन जाने वाला छतरीनुमा गोला है, जो आधे भारत के राज्यों में मंडरा रहा है। इस समय दिल्ली, उप्र, राजस्थान, हरियाणा, मप्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलांगाना में गर्मी एकाएक बढ़ गई है। इस प्राकृतिक स्थिति को ऊष्मा का क्षत्रप (हीट डोम) या गुंबद कहा जा रहा है। यह क्षत्रप तब बनता है, जब वायुमंडल में उच्च दबाव की एक प्रणाली लंबे समय तक किसी एक क्षेत्र में ठहर जाती है। इस समय बर्तन के एक ढक्कन की तरह गर्म हवा ऊष्मा को नीचे धरती की तरफ दवाए रखती है, जो तेज गर्मी का कारण बन जाती है। नतीजतन ऐसे क्षेत्रों में तापमान खतरनाक ढंग से बढ़ जाता है और कई दिनों या हफ्तों तक भीषण गर्मी या लू बनी रहती है। गर्मी की इस प्रचंड स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताया जा रहा है। इस बार गर्मी का मिजाज इसलिए भी अलग है क्योंकि कई तटीय इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में नमी वाली गर्मी यानी उमस का असर भी देखने में आ रहा है। इससे लू लगने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। आधे भारत में बढ़ा तापमान लोगों को पस्त कर रहा है। अतएव हरेक जुबान पर प्रचंड धूप और गर्मी जैसे बोल आमफहम हो गए हैं। हालांकि लू और प्रचंड गर्मी के बीच भी एक अंतर होता है। गर्मी के मौसम में ऐसे क्षेत्र जहां तापमान, औसत तापमान से कहीं ज्यादा हो और पांच दिनों तक यही स्थिति बनी रहे तो इसे 'लू' यानी गर्मी का गोला कहने लगते हैं। मौसम की इस असहनीय विलक्षण दशा में नमी भी समाहित हो जाती है। यही सर्द-गर्म थपेड़े लू की पीड़ा और रोग का कारण बन जाते हैं। किसी भी क्षेत्र का औसत तापमान, किस मौसम में कितना होगा, इसकी गणना एवं मूल्यांकन पिछले 30 साल के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। वायुमंडल में गर्म हवाएं आमतौर से क्षेत्र विशेष में अधिक दबाव की वजह से उत्पन्न होती हैं। वैसे तेज गर्मी और लू पर्यावरण और बारिश के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा मानसून इन्हीं आवारा हवाओं का पर्याय माना जाता है, क्योंकि तपिश और बारिश में गहरा अंतर्संबंध है। धूप और लू के इस जानलेवा संयोग से कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसके लू उतारने के इंतजाम भी किए जाते हैं। दरअसल लू सीधे दिमागी गर्मी को बढ़ा देती है। अतएव इसे समय रहते ठंडा नहीं किया तो यह बिगड़ा अनुपात व्यक्ति को बौरा (पागल) भी सकता है। वैसे शरीर में प्राकृतिक रूप से तापमान को नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क में 'हाइपोथैलेमस' अर्थात 'अधष्चेतक' क्षेत्र करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंत:स्रावी प्रक्रिया के जरिये तापमान को संतुलित बनाए रखना होता है। इसे चिकित्सा शास्त्र की भाषा में हाइपरपीरेक्सिया कहते हैं। यानी शरीर के तापमान में असमान वृद्धि या अधिकतम बुखार का बढ़ जाना। इसकी चपेट में बच्चे और बुजुर्ग आसानी से आ जाते हैं। बाहरी तापमान जब शरीर के भीतरी तापमान को बढ़ा देता है तो हाइपोथैलेमस तापमान को संतुलित बनाए रखने का काम नहीं कर पाता। नतीजतन शरीर के भीतर बढ़ गई अनावश्यक गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जो शरीर में लू का कारण बन जाती है। इस स्थिति में शरीर में कई जगह प्रोटीन जमने लगता है और शरीर के कई अंग एक साथ निष्क्रियता की स्थिति में आने लग जाते हैं। ऐसा शरीर में पानी की कमी यानी डी-हाईड्रेशन के कारण भी होता है। दोनों ही स्थितियां जानलेवा होती हैं। इस स्थिति के निर्माण हो जाने पर बुखार उतारने वाली साधारण गोलियां काम नहीं करती हैं। क्योंकि ये दवाएं दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस को ही अपने प्रभाव में लेकर तापमान को नियंत्रित करती हैं। जबकि लू में यह स्वयं शिथिल होने लग जाता है। हवाएं गर्म का प्रमुख कारण ऋतुचक्र का उलटफेर और भूतापीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) का औसत से ज्यादा बढ़ना है। इसीलिए वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रलय धरती से नहीं आकाशीय गर्मी से आएगी। जिस आकाश को हम निरीह और खोखला मानते हैं, वास्तव में यह खोखला है नहीं। भारतीय दर्शन में इसे पांचवां तत्व यूं ही नहीं माना गया है। सच्चाई है कि यदि परमात्मा ने आकाश तत्व की उत्पत्ति नहीं की होती तो संभवत: आज हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। हम श्वांस भी नहीं ले पाते। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों तत्व आकाश से ऊर्जा लेकर ही क्रियाशील रहते हैं। ये सभी तत्व परस्पर परावलंबी हैं। यानी किसी एक तत्व का वजूद क्षीण होगा तो अन्य को भी छीजने की इसी अवस्था से गुजरना होगा।

महंगाई, ऊर्जा सुरक्षा और नीति निर्माण की चुनौती

- डॉ. प्रियंका सौरभ

पिछले कुछ समय से देश के शहरों और गांवों में एक चिंता लगातार सुनाई दे रही है- पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतें। यह चिंता केवल वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव हर उस नागरिक पर पड़ता है जो रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसका असर केवल पेट्रोल पंप तक नहीं रहता; वह परिवहन, खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री, कृषि लागत और घरेलू बजट तक पहुंच जाता है। इसलिए पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक और नीतिगत प्रश्न भी है, जो सरकार, बाजार और नागरिक- तीनों से जुड़ा हुआ है।

भारत जैसे विकासशील देश में ऊर्जा केवल आर्थिक गतिविधियों का आधार नहीं है बल्कि सामाजिक गतिशीलता और विकास की भी महत्वपूर्ण शक्ति है। देश का विशाल परिवहन तंत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्र बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर हैं। ऐसे में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देता है। यही कारण है कि पेट्रोल के बढ़ते भाव हमेशा जनचर्चा और राजनीतिक बहस का विषय बन जाते हैं।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। देश अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक विदेशों से खरीदता है। इसका अर्थ यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत को अधिक भुगतान करना पड़ता है, और उसका असर अंतत: खुदरा कीमतों में दिखाई देता है।

वैश्विक तेल बाजार केवल आर्थिक कारकों से प्रभावित नहीं होता। इसके पीछे भू-राजनीतिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पश्चिम एशिया में तनाव, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, प्रमुख तेल उत्पादक देशों की उत्पादन नीतियां, रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे कारक तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष या आपूर्ति संकट का असर कुछ ही दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार पर दिखाई देने लगता है। भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि घरेलू बाजार को इन परिस्थितियों से पूरी तरह अलग नहीं रखा जा सकता।हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार एक महत्वपूर्ण कारण है लेकिन पेट्रोल की कीमतों का पूरा सच केवल वहीं तक सीमित नहीं है। भारत में पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा कीमतों में करों की भी बड़ी भूमिका होती है। पेट्रोल की अंतिम कीमत में कच्चे तेल की लागत के अलावा केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क, राज्य सरकारों का मूल्य वर्धित कर (वैट), परिवहन लागत और डीलर कमीशन भी शामिल होता है। यही कारण है कि अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमतें अलग-अलग होती हैं।

तेल पर लगने वाले कर सरकारों के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन करों से प्राप्त आय का उपयोग सड़क निर्माण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्त पोषण में किया जाता है। लेकिन यही कर आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी डालते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है और कर संरचना में कोई राहत नहीं मिलती, तब उपभोक्ताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। यही स्थिति अक्सर राजनीतिक बहस का कारण बनती है।

पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर दिखाई देता है। टैक्सी चालक, ऑटो चालक, ट्रक मालिक, बस संचालक और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लाखों लोग बढ़ती लागत का सामना करते हैं। उनके सामने सामान्यत: दो विकल्प होते हैं- या तो बढ़ी हुई लागत को स्वयं वहन करें अथवा किराए और सेवा शुल्क बढ़ाकर उसका भार उपभोक्ताओं पर डाल दें। अधिकांश मामलों में दूसरा विकल्प अपनाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं।

यहीं से महंगाई का व्यापक प्रभाव शुरू होता है। जब माल ढुलाई महंगी होती है तो सब्जियां, फल, दूध, अनाज, दवाइयां, निर्माण सामग्री और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं भी महंगी होती हैं। इस प्रक्रिया को अर्थशास्त्र में लागत-प्रेरित महंगाई कहा जाता है। इसका असर विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है जबकि खर्च लगातार बढ़ते जाते हैं।

ग्रामीण भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का प्रभाव और भी गहरा होता है। खेती-किसानी आज भी बड़ी मात्रा में डीजल आधारित मशीनों और उपकरणों पर निर्भर है। ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, कटाई मशीनें और कृषि उत्पादों का परिवहन- सभी में ईंधन की आवश्यकता होती है। जब डीजल महंगा होता है तो कृषि लागत बढ़ जाती है। छोटे और सीमांत किसान, जिनकी आय पहले से ही सीमित होती है, इस बढ़ती लागत का सबसे अधिक बोझ उठाते हैं।

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की लागत भी बढ़ जाती है। अक्सर किसान अपने उत्पादों का मूल्य स्वयं निर्धारित नहीं कर पाते और उन्हें बिचौलियों या थोक व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में परिवहन लागत बढ़ने का दबाव किसानों की आय को और कम कर सकता है। परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रभाव पड़ता है- उत्पादन लागत बढ़ती है और लाभ घटता है।

शहरी मध्यम वर्ग भी इस महंगाई से अछूता नहीं रहता। आज का शहरी जीवन डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन खरीदारी, भोजन वितरण और निजी परिवहन पर काफी हद तक निर्भर हो चुका है। लेकिन इन सभी सेवाओं के पीछे परिवहन लागत एक महत्वपूर्ण तत्व है। चाहे कोई ऑनलाइन भोजन मंगाएं या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान खरीदें, अंतत: उसे पहुंचाने वाला वाहन ईंधन पर ही निर्भर होता है। इसलिए पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि धीरे-धीरे उपभोक्ता के दैनिक खर्च को बढ़ाती जाती है।

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करते समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर है। पिछले वर्षों में सरकार ने रणनीतिक तेल भंडार विकसित करने और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास किए हैं। इससे आपूर्ति संकट की स्थिति में कुछ राहत मिल सकती है लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। जब तक देश आयातित तेल पर अत्यधिक निर्भर रहेगा, तब तक वैश्विक बाजार की अस्थिरता का प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ता रहेगा।

यहीं से ऊर्जा स्वाधीनता का प्रश्न सामने आता है। ऊर्जा स्वाधीनता का अर्थ केवल घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाना नहीं है बल्कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को मजबूत करना भी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन और विद्युत आधारित परिवहन व्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

परिवहन नीति भी इस पूरे विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मजबूत, सुलभ और भरोसेमंद हो तो निजी वाहनों पर निर्भरता कम की जा सकती है। मेट्रो, बस रैपिड ट्रांजिट, उपनगरीय रेल और सुरक्षित साइकिल मार्ग जैसे विकल्प न केवल ईंधन की खपत कम कर सकते हैं बल्कि प्रदूषण और यातायात जाम जैसी समस्याओं को भी कम कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश, देश के अनेक शहरों और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं का अभाव अभी भी महसूस किया जाता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य का विकल्प माना जा रहा है। उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है लेकिन चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी लागत और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। यदि सरकारें इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाती हैं और आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करती हैं तो आने वाले वर्षों में तेल पर निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

पेट्रोल की कीमतों का एक पर्यावरणीय आयाम भी है। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण की प्रमुख वजहों में से एक है। बढ़ती ईंधन कीमतें कई बार लोगों को वैकल्पिक परिवहन साधनों की ओर आकर्षित करती हैं लेकिन यह तभी संभव है जब वे विकल्प वास्तव में उपलब्ध और सुविधाजनक हों। केवल कीमत बढ़ा देने से पर्यावरणीय लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते; इसके लिए व्यापक और समन्वित नीति की आवश्यकता होती है।

खेल प्रशासन में ऐतिहासिक बदलाव: केंद्र सरकार ने बनाया राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल न्यायाधिकरण

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय खेल व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम 2026 और राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से मंगलवार सुबह जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इन नए नियमों के लागू होने के बाद देश में खेल संघों की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और खेल विवादों के निपटारे की व्यवस्था पूरी तरह बदलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे खेल प्रशासन अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और पेशेवर बनेगा। नए नियमों के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

मप्र के एथलेटिक्स खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन, देव मीणा ने जीता स्वर्ण

भोपाल। झारखंड के रांची में 22 मई से आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 14:15.50 सेकेंड का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अर्जित किया। वहीं शॉटपुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने 20.46 मीटर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतकर अकादमी को एक और बड़ी सफलता दिलाई। कॉमनवेल्थ गेम्स एवं एशियन गेम्स के लिए हासिल किया क्वालीफाइंग मार्क देव मीणा और कुलदीप कुमार ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए निर्धारित 5.25 मीटर क्वालीफाइंग मार्क को पार करते हुए प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स के लिए निर्धारित 5.45 मीटर क्वालीफाइंग मानक भी हासिल कर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। यह उपलब्धि मध्य प्रदेश एवं देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है।

मप्र के एथलेटिक्स खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन, देव मीणा ने जीता स्वर्ण

भोपाल। झारखंड के रांची में 22 मई से आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 14:15.50 सेकेंड का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अर्जित किया। वहीं शॉटपुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने 20.46 मीटर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतकर अकादमी को एक और बड़ी सफलता दिलाई। कॉमनवेल्थ गेम्स एवं एशियन गेम्स के लिए हासिल किया क्वालीफाइंग मार्क देव मीणा और कुलदीप कुमार ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए निर्धारित 5.25 मीटर क्वालीफाइंग मार्क को पार करते हुए प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स के लिए निर्धारित 5.45 मीटर क्वालीफाइंग मानक भी हासिल कर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है।

ब्रास सिटी इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट में रुक्मणी ब्लू सात विकेट से विजयी

मुरादाबाद। ब्रास सिटी इंटर क्लब क्रिकेट मुकाबले में रुक्मणी ब्लू ने रुक्मणी रेड को सात विकेट से पराजित कर दमदार जीत दर्ज की। मैच में बेहतरीन गेंदबाजी के लिए रुक्मणी ब्लू के शहरान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रुक्मणी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रुक्मणी रेड की टीम 28.3 ओवर में 135 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से अनस ने 40 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जबकि मो. शाकिब ने 35 और मो. शान

ने 17 रन का योगदान दिया। रुक्मणी ब्लू की ओर से शहरान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट झटके। लकी चौधरी, मो. शान और सल्लू ने दो-दो विकेट हासिल किए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी रुक्मणी ब्लू की टीम ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 22.5 ओवर में तीन विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की जीत के हीरो फहद खान रहे, जिन्होंने नाबाद 67 रन की शानदार पारी खेली। हरेंद्र कुमार ने 35 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। अलीम चौधरी नौ और मो. अर्श सात रन बनाकर नाबाद लौटे। रुक्मणी रेड की ओर से आजाद सिंह ने दो और मो. शाकिब ने एक विकेट हासिल किया।

आईएयू 24 एच एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत का दबदबा, अमर सिंह ने जीता गोल्ड

एजेंसी

नई दिल्ली। जापान में आईएयू 24 एच एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल पांच मेडल जीते। वहीं, पुरुषों की व्यक्तिगत इवेंट में क्लीन स्वीप किया। भारतीय पुरुष टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा किया और कुल 815.833 किलोमीटर की दूरी तय करके टीम गोल्ड मेडल हासिल किया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा, 'भारतीय अल्ट्रा रनिंग के लिए इतिहास। फिर से एशिया-ओशिनिया के चैंपियन। 2022, 2024 और अब 2026।' 23 से 24 मई तक 24 घंटे की कड़ी

रेसिंग में, टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। नतीजों में अमर सिंह देवंदा की अगुवाई में भारतीय पुरुष टीम ने धैर्य का शानदार परिचय दिया। अमर सिंह देवंदा ने 282.881 किलोमीटर की शानदार दूरी के लिए 226 लैप पूरे करके गोल्ड मेडल जीता, गीनो एंटनी ने 272.894 किलोमीटर (218 लैप) के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। मेजबान देश जापान ने मासाकी किमोटो की अगुवाई में टीम सिल्वर (754.726 किलोमीटर) अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने फिल गोर के 253.392 किलोमीटर के शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम ब्रॉन्ज (732.525 किलोमीटर) पर कब्जा जमाया। महिलाओं की कैटेगरी में, भारतीय महिला टीम ने अपने फेडरेशन के लिए एक बहुत सफल सप्ताहांत का अंत टीम ब्रॉन्ज (667.722 किलोमीटर) जीतकर किया, जिसमें तेनजिन डोल्मा (228.939 किलोमीटर) ने शानदार चौथा व्यक्तिगत स्थान हासिल किया। जापान की मिहो नाकाटा ने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल 20 किलोमीटर के बड़े अंतर से जीता, 208 लैप पूरे करके 261.170 किलोमीटर की दूरी तय की। उनके प्रदर्शन की वजह से जापानी महिला टीम ने कुल 707.357 किलोमीटर की दूरी तय करके गोल्ड मेडल जीता। ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल (684.450 किलोमीटर) को अपने नाम किया। कुल मिलाकर 81 एथलीट (39 महिलाएं / 42 पुरुष) ने 9 फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किया।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए कोलंबिया टीम घोषित, जेम्स रोड्रिगेज को मिली जगह

एजेंसी

नई दिल्ली। कोलंबिया ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए अपनी 26 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। टीम में पूर्व रियल मैड्रिड स्टार जेम्स रोड्रिगेज को शामिल किया गया है, जबकि अल नास्र के डिफेंडर जॉन दुरान को जगह नहीं मिली। मुख्य कोच नेस्टर लोरेन्जो की टीम में बायर्न म्यूनिख के स्टार फॉरवर्ड लुइस डियाज़ सबसे बड़े आकर्षण होंगे। कोलंबिया इस बार पहली बार विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। कोलंबिया वर्ष 2022 विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया था। वहीं 2018 विश्व कप में टीम इंग्लैंड के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हारकर प्री-क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई थी। कोलंबिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 विश्व कप में रहा था, जब टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी और ब्राजील से हार गई थी। विश्व कप 2026 में कोलंबिया को ग्रुप-के में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला पुर्तगाल, उज्बेकिस्तान और डीआर कांगो से होगा।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए कोलंबिया की टीम

गोलकीपर: कैमिलो वर्गास, अल्वारो मोंटेरो, डेविड ओस्पिना

डिफेंडर: डेविंसन सांचेज, जॉन लुकुमी, येरी मीना, विलियम डिट्टा, डेनियल मुनोज, सैंटियागो आरियास, जोहान मोजिका, डेविन मचाडो

मिडफील्डर:

जेफरसन लेर्मा, जुआन पोर्टिला, रिचर्ड रियोस, केविन कास्टानो, गुस्तावो पुर्ता, जॉन एरियास, जॉर्ज कारास्कल, जुआन फर्नांडो किंटेरो, जेम्स रोड्रिगेज

फॉरवर्ड: लुइस डियाज़, जामिंटन कैंपाज, एंड्रेस गोमेज, लुइस सुआरेज़, जॉन कॉर्डोबा, जॉन हर्नांडेज़।

ट्रेविस हेड की पत्नी ने बताया, कोहली से झगड़े के बाद परिवार की हुई ट्रोलिंग

एजेंसी

एडिलेड। ट्रेविस हेड और विराट कोहली के बीच पिछले हफ्ते आईपीएल 2026 के मैच के दौरान मैदान पर तकरार देखने को मिली थी, जिसके बाद ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका ने बताया है कि उनके परिवार और दोस्तों को आपत्तिजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो कोहली और हेड के बीच कुछ कहा-सुनी हुई। जब सनराइजर्स हैदराबाद ने 55 रनों से जीत दर्ज कर ली, तो हेड ने मैच के बाद कोहली से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन कोहली बिना कोई जवाब दिए उनके पास से गुजर गए और हाथ मिलाने से मना कर दिया, जबकि उन्होंने एसआरएच के दूसरे खिलाड़ियों से सामान्य अंदाज में हाथ मिलाया। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। जेसिका ने 'द एडवरटाइजर' से कहा, 'ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप के बाद जो हमें जिस तरह आपत्तिजनक टिप्पणियों का सामना

करना पड़ा था, वही फिर से हो रहा है। जब मैं सुबह उठी तो देखा कि मेरे सोशल मीडिया पर अभद्र शब्दों की बाढ़ आई हुई है। हम तो ठीक हैं, लेकिन वे मेरे दोस्तों और परिवार पर हमला कर रहे हैं।'

जेसिका ने यह भी बताया कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और साल 2024 के बॉक्सिंग डे टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, तब भी उन्हें इस तरह की अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था। जेसिका ने फैंस से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर क्रिकेटर्स और उनके परिवारों के प्रति अधिक सम्मानजनक रवैया अपनाएं।

जेसिका ने कहा, 'मुझे लगता है कि इस समय सभी खेलों में मानसिक स्वास्थ्य, नजरिए और हम एक-दूसरे से कैसे बात करते हैं, इस पर एक जरूरी बातचीत चल रही है। जुनून हमेशा खेल का हिस्सा रहेगा, लेकिन यह याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि खेल के पीछे असली लोग और परिवार भी होते हैं। उम्मीद है कि इससे एक-दूसरे के प्रति ज्यादा दयालुता और समर्थन को बढ़ावा मिलेगा। 'रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 26 मई को धर्मशाला में गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-2 खेलेगी, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 27 मई को एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना करेगी।

सुआरेज की हैट्रिक, इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया को 6-4 से हराया

एजेंसी

मियामी। इंटर मियामी सीएफ ने एमएलएस रेगुलर सीजन एक्शन में फिलाडेल्फिया यूनियन के खिलाफ 6-4 से रोमांचक दर्ज की। लुइस सुआरेज की हैट्रिक, जर्मन बर्टेराम के दो गोल और मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल के एक गोल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ब्रेक से पहले मियामी की इस रेगुलर सीजन में चौथी जीत दिलाई। मैच की शुरुआत फिलाडेल्फिया ने शानदार अंदाज में की और चौथे मिनट में ही पहला गोल किया। इसके बाद 10वें मिनट में फिलाडेल्फिया ने दूसरा गोल दागते हुए मैच में अपनी बढ़त को 2-0 कर दिया। इंटर मियामी ने 13वें मिनट में पहला गोल किया। बर्टेराम ने बॉक्स के अंदर मेसी के सटीक असिस्ट का फायदा उठाते हुए पास से गोल किया। इंटर मियामी की रिपोर्ट के अनुसार, यह गोल बर्टेराम का इस रेगुलर सीजन में छठा गोल था, जबकि मेसी का यह सातवां असिस्ट रहा। मेहमान टीम ने 20वें मिनट में एक और गोल दागा और स्कोरलाइन 1-3 कर दी।

हालांकि, सुआरेज ने इंटर मियामी की वापसी कराई और मैच के 29वें मिनट में शानदार वॉली लगाकर गोल किया। मियामी ने 42वें मिनट में बराबरी का गोल किया, जब बर्टेराम ने इस रेगुलर सीजन में अपना सातवां और इंटर मियामी के लिए अपना पहला गोल किया। मेसी ने बॉक्स के ऊपर से बर्टेराम को शानदार पास दिया, जिसके बाद मैक्सिको के खिलाड़ी ने पहली बार दाहिने पैर से फिनिश करते हुए बॉल को नेट में डाल दिया।इसके बाद मेजबान टीम ने 44वें मिनट में ब्रेक से ठीक पहले मैच में पहली बार बढ़त हासिल की। सुआरेज ने डी पॉल के शुरुआती प्रयास के बाद पास से गोल किया। हालांकि, फिलाडेल्फिया ने स्टॉपेज टाइम के आठवें मिनट में चौथा गोल करते हुए स्कोर को 4-4 से बराबर कर दिया। इंटर मियामी ने 81वें मिनट में फिर से बढ़त हासिल की। बर्टेराम का पहला शॉट बॉक्स के अंदर ही रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने गोल के सामने सुआरेज को पास दिया और सुआरेज ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया और अपनी हैट्रिक पूरी की। सुआरेज ने अब तक इस रेगुलर सीजन में 6 गोल किए हैं, जबकि बर्टेराम ने 4 असिस्ट दिए हैं। मेजबान टीम के लिए छठा गोल डी पॉल ने किया और टीम की जीत पर मुहर लगा दी।

प्रग्गनानंदा और गुकेश ने आर्मागेडन में दर्ज की जीत, दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया

एजेंसी

ओस्लो। नॉर्वे चेस 2026 की शुरुआत ओस्लो में काफी रोमांचक अंदाज में हुई। भारतीय खिलाड़ी आर प्रग्गनानंदा और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश दोनों ने अपने-अपने पहले क्लासिकल मैच ड्रॉ खेले। इसके बाद हुए आर्मागेडन टाई-ब्रेक में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल करके अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। वहीं, दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन वेनजुन को शिकस्त दी। प्रग्गनानंदा ने आक्रामक प्रदर्शन के साथ टाईब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, तो गुकेश ने क्लासिकल मुकाबले में मुश्किल एंडगेम से बचने के बाद विंसेंट कीमर के खिलाफ शानदार वापसी की। हालांकि, शुरुआती राउंड का सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब अलीरेजा फिरौजा ने क्लासिकल चेस में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को चौंका दिया, जिससे नॉर्वे के सुपरस्टार को घरेलू मैदान पर एक दुर्लभ हार का सामना करना पड़ा।

प्रग्गनानंदा और वेस्ली सो ने एक संतुलित क्लासिकल गेम खेला जो एक तनावपूर्ण मुकाबले के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इसके बाद आर्मागेडन टाई-ब्रेक में प्रग्गनानंदा ने तेज और आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने खेल की गति बढ़ाई और लगातार दबाव बनाते हुए बेहतर चालें खेलीं, जिससे उन्हें बोनस प्वाइंट्स हासिल करने में मदद मिली और उन्होंने निर्णायक गेम अपने नाम कर लिया। एक और बेहद रोमांचक मुकाबले में गुकेश का सामना जर्मनी के विंसेंट कीमर से हुआ। मैच के एंडगेम में ऐसा लग रहा था कि कीमर जीत के करीब हैं और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश मुश्किल में पड़ गए हैं, लेकिन गुकेश ने शानदार धैर्य और मजबूत डिफेंस दिखाते हुए हार टाल दी और मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रहे। इसके बाद आर्मागेडन टाई-ब्रेक में उन्होंने उसी आत्मविश्वास के साथ खेल जारी रखा और बाजी पलटते हुए शानदार जीत दर्ज की। कार्लसन पर फिरोजा की जीत दिन का सबसे अहम नतीजा साबित हुई। कार्लसन गेम के ज्यादातर हिस्से में कंट्रोल में दिखे, लेकिन समय की बहुत ज्यादा दिक्कत की वजह से एक बड़ी गलती कर बैठे, जिसका पूरा फायदा फ्रेंच ग्रैंडमास्टर ने उठाया और ओपन सेक्शन में इकलौती क्लासिकल जीत दर्ज की।

महिला टूर्नामेंट में, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जू वेनजुन और दिव्या देशमुख का मैच भी तनाव से भरे मुकाबले के बाद ड्रॉ पर खत्म हुआ। दिव्या ने आर्मागेडन के निर्णायक गेम में जबरदस्त प्रदर्शन किया और आर्मागेडन टाईब्रेक गेम जीत लिया। वहीं, बिबिसारा अस्सौबायेवा ने क्लासिकल शतरंज में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को मात दी। एना मुजीचुक और झू जिनर ने अपना क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ किया, जिसके बाद झू आर्मागेडन में जीतकर अतिरिक्त पॉइंट हासिल करने में सफल रहीं। मौजूदा महिला वर्ल्ड चैंपियन जू वेनजुन को भी भारत की दिव्या देशमुख ने ड्रॉ पर रोका, जिन्होंने बाद में आर्मागेडन में उन्होंने जीत हासिल करके सभी को प्रभावित किया।

मेग लैनिंग ने विक्टोरिया अनुबंध छोड़ अपनाया फ्रीलांस क्रिकेटर का रास्ता

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग ने अगले सत्र के लिए विक्टोरिया का अनुबंध नहीं लेने का फैसला किया है और अब वह फ्रीलांस क्रिकेटर के रूप में खेलती नजर आएंगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी लैनिंग विक्टोरिया टीम का हिस्सा बनी हुई थीं, लेकिन पिछले सत्र में उन्होंने टीम के लिए केवल चार मुकाबले खेले थे। महिला बिग बैश लीग के बाद वह किसी भी मैच में नहीं उतरीं। मेग लैनिंग इस समय दुनिया की विभिन्न फ्रेंचाइजी लीगों में खेल रही हैं। वह महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स, द हंड्रेड में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और इस सत्र में लंकाशायर के लिए टी-20 ब्लास्ट में हिस्सा ले चुकी हैं।

लैनिंग फिलहाल मेलबर्न स्टार्स के साथ भी अनुबंधित नहीं हैं। हालांकि पिछले महिला बिग बैश लीग सत्र में वह टीम की दूसरी सबसे सफल बल्लेबाज रहीं। उन्होंने 53.22 की औसत और 136.07 के स्ट्राइक रेट से 479 रन बनाए थे। क्रिकेट विक्टोरिया की महिला क्रिकेट प्रमुख किर्बी शॉर्ट ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, 'हम मेग के फैसले का सम्मान करते हैं। महिला क्रिकेट तेजी से विकसित हो रहा है और खिलाड़ियों को अब दुनिया भर में खेलने के अवसर मिल रहे हैं। यह हमारे खेल के विकास का सकारात्मक संकेत है।' किर्बी शॉर्ट ने स्वीकार किया कि 2025-26 सत्र विक्टोरिया के लिए बेहद निराशाजनक रहा, जहां टीम अपने सभी 12 मुकाबले हार गई थी। उन्होंने कहा, 'हम पिछले सत्र के परिणामों पर गर्व नहीं कर सकते और हमें पता है कि हमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हालांकि समीक्षा के बाद खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच सकारात्मक माहौल बनाने को लेकर स्पष्ट समझ बनी है।' उन्होंने आगे कहा कि टीम धीरे-धीरे सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है और रातोंरात बदलाव की उम्मीद नहीं कर रही।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को 'पद्म श्री' से सम्मानित किया

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'पद्म श्री' से सम्मानित किया। इस साल सम्मानित होने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में हरमनप्रीत भी शामिल थीं। उनके साथ भारतीय पुरुष टीम के दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी यह सम्मान मिला।

हरमनप्रीत कौर को यह सम्मान भारतीय क्रिकेट में उनके शानदार योगदान और 'विमेन इन ब्लू' को अंतरराष्ट्रीय सफलताएं दिलाने में उनके नेतृत्व को देखते हुए दिया गया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साल 2025 में अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला खिताब

जीता था। यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में पद्म पुरस्कार प्रदान किए, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं। कुल मिलाकर, साल 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है।

इससे पहले, जब पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा की गई थी, तब हरमनप्रीत ने अपनी विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) टीम मुंबई इंडियंस की तरफ से साझा किए गए एक वीडियो में आभार व्यक्त करते हुए इस क्षण को अपने परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया था। फ्रेंचाइजी की तरफ से साझा किए गए एक वीडियो में हरमनप्रीत कौर ने कहा था, 'मेरे पिताजी को राष्ट्रपति भवन से फोन आया। इस साल मुझे पद्म श्री पुरस्कार मिलने वाला है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है। मुझे खुशी है कि, मुझसे पहले मेरे माता-पिता को इस बारे में पता चला।' उन्होंने सम्मान सूची में रोहित शर्मा के शामिल होने पर भी खुशी जताई और कहा, '(रोहित शर्मा) को भी बहुत-बहुत बधाई। हमने देखा है कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है। मुझे लगता है कि यह उनके लिए भी एक शानदार क्षण है।'

37 वर्षीय हरमनप्रीत भारत की तरफ से 195 टी20 मुकाबलों में 29.78 की औसत के साथ 3,991 रन बना चुकी हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है। 164 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 7 शतकों के साथ 4,541 रन बनाए हैं। 7 टेस्ट मुकाबलों में दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 230 रन जुटाए हैं।

बुंडेसलीगा से 29 साल बाद बाहर हुआ वोल्फ्सबर्ग, पैडरबोर्न ने अतिरिक्त समय में दर्ज की ऐतिहासिक जीत

एजेंसी

पैडरबोर्न। जर्मन फुटबॉल क्लब वोल्फ्सबर्ग 29 वर्षों बाद बुंडेसलीगा से बाहर हो गया। खेले गए रेलिगेशन प्लेऑफ के दूसरे चरण में पैडरबोर्न ने अतिरिक्त समय में 2-1 से जीत दर्ज कर शीर्ष लीग में जगह बना ली। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला गोलरहित ड्रॉ रहा था। दूसरे चरण में वोल्फ्सबर्ग ने तीसरे मिनट में डेजनान पेजचिनोविच के गोल की बदौलत बढ़त बना ली थी, लेकिन पैडरबोर्न ने पहले हाफ खत्म होने से सात मिनट पहले फिलिप बिलबिजा के गोल से बराबरी कर ली। मुकाबले में वोल्फ्सबर्ग की मुश्किलें तब बढ़ गई जब जोआकिम मेहले को शुरुआती गोल के केवल 11 मिनट बाद रेड कार्ड दिखाया गया। उन्हें तीन मिनट के भीतर दो पीले कार्ड मिले और टीम को लगभग पूरा मैच 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बाद पैडरबोर्न ने लगातार आक्रमण किए, लेकिन वोल्फ्सबर्ग के गोलकीपर कामिल ग्राबारा ने कई शानदार बचाव कर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 रहने के बाद मैच अतिरिक्त समय में पहुंचा। अतिरिक्त समय के 10वें मिनट में लॉरिन कुर्डा ने शानदार वॉली गोल दागकर पैडरबोर्न को निर्णायक बढ़त दिलाई। यही गोल टीम की ऐतिहासिक जीत का कारण बना और पैडरबोर्न ने तीसरी बार बुंडेसलीगा में प्रवेश किया। वोल्फ्सबर्ग 1997 में पहली बार बुंडेसलीगा में पहुंचा था

और तब से लगातार शीर्ष लीग का हिस्सा रहा। क्लब ने 2009 में बुंडेसलीगा खिताब और 2015 में जर्मन कप जीता था। वहीं पैडरबोर्न की इससे पहले बुंडेसलीगा में दो बार एंट्री हुई थी, लेकिन दोनों मौकों पर टीम अगले ही सत्र में बाहर हो गई थी।

जिला कांगड़ा एथलेटिक्स मीट 3 जून को धर्मशाला में

एजेंसी

धर्मशाला। जिला कांगड़ा एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन 3 जून 2026 को सिंथेटिक स्टेडियम धर्मशाला में किया जाएगा। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के लड़के एवं लड़कियां भाग ले सकेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने बताया कि अंडर-14 वर्ग में 60 मीटर एवं 600 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉटपुट तथा ट्रायथलन-ए, बी और सी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। वहीं अंडर-16 वर्ग में 60 मीटर, 600 मीटर दौड़, शॉटपुट एवं लॉन्ग जंप स्पर्धाएं होंगी। उन्होंने बताया कि अंडर-18 वर्ग में 100, 200, 400 एवं 1000 मीटर दौड़, शॉटपुट तथा लॉन्ग जंप प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। अंडर-20 वर्ग में 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 एवं 5000 मीटर दौड़ के साथ शॉटपुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप तथा ट्रिपल जंप प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पुरुष एवं महिला वर्ग में 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 एवं 10000 मीटर दौड़ के अलावा शॉटपुट, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप तथा हाई जंप प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को सुबह 9 बजे अपनी किट, आयु प्रमाण पत्र तथा 200 रुपये पंजीकरण शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा। विक्रम चौधरी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आधार पर जिला कांगड़ा की टीम का चयन किया जाएगा।

अंडर-18 एशिया कप : भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम जापान के लिए हुई रवाना

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत की अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी टीमें 29 मई से 6 जून तक होने वाले अंडर-18 एशिया कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए जापान के काकामिगाहारा के लिए रवाना हो गई हैं। पुरुषों की टीम सोमवार शाम को नई दिल्ली से रवाना हुई जबकि महिलाओं की टीम मंगलवार सुबह रवाना हुई। दोनों टीमों ने भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के उद्धव दास मेहता सेंटर में एक महीने तक चले नेशनल कोचिंग कैंप में हिस्सा लिया। पुरुषों की टीम ने कोच सरदार सिंह और रजनीश मिश्रा के अंडर ट्रेनिंग की जबकि भारत की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने महिला टीम के कैंप को अधीक्षण किया। अपनी आखिरी तैयारियों के हिस्से के तौर पर भारत की जूनियर टीमों ने भोपाल में मेहमान ऑस्ट्रेलियाई अंडर-18 टीमों के खिलाफ चार मुकाबलों की एक्सपोज़र सीरीज खेली। भारतीय पुरुष टीम ने एक मैच में जीत दर्ज की, तो एक में टीम को हार झेलनी पड़ी है। वहीं, दो मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए। महिलाओं की टीम ने एक शानदार जीत के साथ अपनी सीरीज का अंत किया। इन मैचों से महाद्वीप

टूर्नामेंट से पहले कीमती इंटरनेशनल अनुभव मिला। फॉरवर्ड केतन कुशवाहा की अगुवाई में भारतीय पुरुषों की टीम को पूल ए में कजाकिस्तान, मेजबान जापान, कोरिया और चीनी ताइपे के साथ रखा गया है। भारत अपने कैंपेन की शुरुआत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ करेगा, जिसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे से भिड़ेगा। पुरुषों की प्रतियोगिता में पूल बी में मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन हैं। हर पूल से टॉप दो टीमें 5 जून को सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, और फाइनल 6 जून को होगा। रवाना होने से पहले, केतन कुशवाहा ने टूर्नामेंट में जाने से पहले टीम की तैयारियों और आत्मविश्वास के बारे में बात की। 'एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करना हम सभी के लिए बहुत बड़े सम्मान और जिम्मेदारी की बात है।

हमने भोपाल में कैंप के दौरान बहुत मेहनत की है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। टीम ने मैदान पर और मैदान के बाहर अच्छी समझ बनाई है, और हम एशिया की कुछ सबसे अच्छी युवा टीमों के खिलाफ खुद को परखने के लिए उत्साहित हैं। हमें पूरा भरोसा है और हम हर मैच में अपना बेस्ट देंगे।' स्वीटी कुजूर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम ने भोपाल में ट्रेनिंग कैंप के दौरान कॉम्बिनेशन, मैच फिटनेस और सामरिक निष्पादन पर बहुत ध्यान दिया। पूल ए में शामिल महिला टीम 30 मई को मलेशिया के खिलाफ अपना एशिया कप कैंपेन शुरू करेगी और फिर 31 मई को टीम का सामना कोरिया से होगा। भारत 2 जून को सिंगापुर के खिलाफ ग्रुप स्टेज खत्म करेगी। पुरुष टीम के फॉर्मेट की तरह हर पूल से टॉप दो टीमें 5 जून को सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जिसके एक दिन बाद खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।

एलआईसी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.06 फीसदी की

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.06 फीसदी कर ली है। पहले यह हिस्सेदारी 3.16 फीसदी थी। सेंट्रल बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि एलआईसी ने 22 मई को बाजार खरीद के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता में 26.26 करोड़ शेयर यानी 2.90 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। इस अधिग्रहण के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़कर 6.06 फीसदी हो गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 0.03 फीसदी की गिरावट के साथ 31.29 रुपये पर बंद हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार की चार फीसदी हिस्सेदारी के लिए बिक्री पेशकश (ओएफएस) को संस्थागत निवेशकों से शुक्रवार को 2,380 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां मिलीं थीं।

खान सचिव ने खनिज ब्लॉक की नीलामी और उसके संचालन की प्रगति की समीक्षा की

नई दिल्ली। खान मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल ने खनिज ब्लॉक की नीलामी और उनके परिचालन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में नीलाम किए गए ब्लॉकों के संचालन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। खान मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि सचिव पीयूष गोयल ने मंत्रालय और श्रेणी-ए खनिज उत्पादक राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देशभर में खनिज ब्लॉकों की नीलामी और उनके संचालन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित नौवीं मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में खनन क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने, घरेलू खनिज उत्पादन बढ़ाने और नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंत्रालय के मुताबिक समीक्षा बैठक के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2015 में नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान कुल 108 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। इसके बाद नीलामी की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच 364 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई, जो प्रति वर्ष औसतन लगभग 90 ब्लॉक है।

उदय कोटक को बैंकिंग क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया पद्म भूषण सम्मान

नई दिल्ली। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय सुरेश कुमार कोटक को वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान न केवल उदय कोटक की व्यक्तिगत व्यावसायिक सफलता को दर्शाता है, बल्कि देश के व्यापार और उद्योग क्षेत्र की मजबूती और अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की भूमिका को भी सर्वोच्च स्तर पर मान्यता देता है। इसके अलावा वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कार सोलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल, दास ऑफशोर इंजीनियरिंग के अशोक खाड़े और टीटीके ग्रुप के चेयरमैन टीटी जगन्नाथन (मरणोपरांत) को यह पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो देश के लिए की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा को मान्यता प्रदान करता है।

पेप्सिको का लेज मिनी स्टिक्स अब उत्तर और पश्चिम भारत में भी उपलब्ध

नई दिल्ली। पेप्सिको इंडिया ने अपने लोकप्रिय स्नैक ब्रांड 'लेज' का नया स्टिक-फॉर्मेट 'लेज मिनी स्टिक्स' का विस्तार अब उत्तर और पश्चिम भारत के बाजार में किया है। यह उत्पाद अब उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत के बाजारों में जनरल ट्रेड स्टोर्स पर 5 रुपये और 10 रुपये की किफायती कीमत में उपलब्ध है। पेप्सिको इंडिया का यह नया करारा स्टिक-फॉर्मेट स्नैक अब उन बाजारों में अपनी जगह बना रहा है, जहां हर बाइट में मसालों का स्वाद और साथ मिलकर खाने का मजा उपभोक्ताओं को खूब पसंद आता है। कंपनी ने इससे पहले पूर्वी भारत में लेज मिनी स्टिक्स की शानदार शुरुआत की थी। दशकों से लेज अपने आइकॉनिक आलू चिप्स और यादगार फ्लेवर अनुभवों के लिए जाना जाता रहा है, जिसने भारतभर के उपभोक्ताओं के स्नैकिंग पलों को खास बनाया है। लेज मिनी स्टिक्स के साथ पेप्सिको इंडिया ब्रांड ने अपने लोकप्रिय आलू स्नैकिंग अनुभव को नए स्टिक फॉर्मेट में पेश किया है, जो परिचित नमकीन स्वाद के साथ मजेदार और करारे क्रंच का नया ट्विस्ट लेकर आया है। लॉन्च के बारे में बात करते हुए मुख्य विपणन अधिकारी, फूड्स, पेप्सिको इंडिया, साक्षी वर्मा मेनन ने कहा, 'पेप्सिको इंडिया में हमारी विकास रणनीति हमेशा उपभोक्ताओं की पसंद और बदलती जरूरतों को समझने पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि भारत में स्नैकिंग का तरीका तेजी से बदल रहा है, जहां भागदौड़ भरी इस जीवनशैली के बीच लोग ऐसे स्नैक्स चाहते हैं, जिन्हें कहीं भी और कभी भी आसानी से आनंद लिया जा सके। ऐसे में आलू चिप्स श्रेणी में अग्रणी ब्रांड होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बदलाव के साथ चलने की नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की भी है। लेज मिनी स्टिक्स हमारे इसी 'इनोवेशन-फर्स्ट' विज़न का बेहतरीन उदाहरण है।

तेलंगाना ने एलएंडटी से खरीदी हैदराबाद मेट्रो, आईआरएफसी से लिया 13,527 करोड़ रु. का ऋण

एजेंसी

नई दिल्ली । तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो का लार्सन एंड टूब्रो मेट्रो रेल लिमिटेड से अधिग्रहण कर लिया है और इसके लिए रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) से साढ़े 13 हजार करोड़ रुपये का किफायती ऋण लिया है। आईआरएफसी ने यहां एलएंडटी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड के साथ 13,527 करोड़ रुपये के एक ऐतिहासिक टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईआरएफसी के सीएमडी एवं सीईओ मनोज कुमार दुबे तथा तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह पुनर्वित्तपोषण एलएंडटी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड के 100 प्रतिशत स्वामित्व को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड

से हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के माध्यम से तेलंगाना सरकार को हस्तांतरित किए जाने के बाद किया जा रहा है। इस हस्तांतरण के बाद अब हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन परिसंपत्ति बन गया है, जिससे इसके चरणबद्ध विस्तार के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार होगा। इसे देश के शहरी परिवहन क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण पुनर्वित्त (रिफाइनेंसिंग) लेन-देन में से एक माना जा रहा है। दुबे के अनुसार इस सौदे में ऋण की राशि 13,527 करोड़ रुपये होगी। ऋण की अवधि 20 वर्ष होगी और इसे त्रैमासिक भुगतान संरचना के साथ चुकता किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना की ऋण देनदारियों के पुनर्वित्तपोषण की परियोजना प्रोसेसिंग फीस, कमिटमेंट चार्ज या प्री-पेमेंट पेनल्टी से पूरी तरह मुक्त होगी। इस सौदे के बारे में दुबे ने कहा कि इस लेन-देन को बेहद मजबूत सुरक्षा ढांचा प्रदान किया गया है। इसके तहत तेलंगाना सरकार द्वारा आईआरएफसी के सभी भुगतानों के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय आश्वासन, राज्य सरकार की गारंटी तथा रिजर्व बैंक समर्थित डायरेक्ट डेबिट मैकेनिज्म शामिल हैं। मनोज कुमार दुबे ने कहा, यह लेन-देन दर्शाता है कि बड़े पैमाने की शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को भारत में ही दीर्घावधि और कुशल वित्तीय संरचनाओं के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है।

अब सीएनजी की कीमत बढ़ी, दिल्ली में हुई प्रति किलोग्राम 83.09 रुपये

एजेंसी

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के ठीक एक दिन बाद आज सीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया है। आज से सीएनजी की दर 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है। 15 मई के बाद यह चौथी बढ़ोतरी है। इस बदलाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

इससे पहले सीएनजी की कीमत में 15 मई को 2 रुपये, 18 मई को 1 रुपया, और 23 मई को 1 रुपया की बढ़ोतरी की गई थई। इसका असर सबसे अधिक दिल्ली-एनसीआर में देखने को मिल सकता है। यहां ऑटो, टैक्सी, स्कूल वैन और प्राइवेट कारों में सीएनजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि से परिवहन लागत और घरेलू बजट पर दबाव बढ़ने की आशंका है यह वृद्धि मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण देखने को मिल रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों का

आवागमन प्रभावित है। मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच करीब 12 हफ्ते से टकराव जारी है। इस कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। कल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल के बाद इस साल पहली बार कीमतें 100 रुपये के पार चली गईं।

आगामी खरीफ सत्र के लिए देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता: सरकार

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा कि आगामी खरीफ सत्र के लिए देश में उर्वरकों की उपलब्धता के साथ इनकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार ने कहा कि खरीफ सत्र के लिए कुल आवश्यकता 390.54 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) आंकी गई है, जिसके मुकाबले में 200.12 एलएमटी का स्टॉक उपलब्ध है।

उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन अच्छा रहा है, और इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयात भी किया जा रहा है। अतिरिक्त सचिव, अपर्णा एस. शर्मा ने कहा कि इस साल के लिए 390.54 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के अनुमान के मुकाबले देश में उर्वरकों की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मौजूदा स्टॉक 200.12 लाख मीट्रिक टन है, जो 51 फीसदी से

अधिक है और सामान्य स्तर 33 फीसदी से काफी अधिक है।अपर्णा एस. शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद घरेलू उत्पादन और उर्वरक आयात काफी ज्यादा रहा है। उन्होंने कहा कि कुल घरेलू उत्पादन लगभग 95 लाख मीट्रिक टन रहा है, और करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयात हमारे देश में पहुंचा है। इस तरह कुल मिलाकर समग्र उपलब्धता में 117.6 लाख मीट्रिक टन उर्वरक जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि देश ने 13.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 9 लाख मीट्रिक टन एनपीके कॉम्प्लेक्स भी हासिल किए हैं, जो खरीफ मौसम के चरम समय के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

एथेनॉल आधारित स्टोव पर खाना बनाने की लागत एलपीजी से कम : नितिन गडकरी

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल आधारित स्वदेशी कुकिंग स्टोव टेक्नोलॉजी का अनावरण किया और कहा कि इस स्वदेशी स्टोव पर कमर्शियल एलपीजी की तुलना में कम कीमत पर खाना बनाया जा सकता है। साथ ही, उन्होंने युवा भारतीयों की विज्ञान में रुचि को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपए की एक पहल की घोषणा भी की। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि नई तकनीक में खाना पकाने के लिए उपयुक्त लौ उत्पन्न करने के लिए एथेनॉल और पानी के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। मंत्री ने कहा, 'पानी में 7 प्रतिशत एथेनॉल मिलाकर स्टोव से लौ उत्पन्न की जा सकती है, और यह खाना पकाने वाली गैस से सस्ती है। यह हमारे देश में ही विकसित की गई है। ' यह घोषणा जीवाश्म ईंधन के टिकाऊ और किफायती विकल्प के रूप में एथेनॉल के लिए गडकरी के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के अनुरूप है। पिछले कई वर्षों से, उन्होंने परिवहन और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में यह तर्क देते हुए एथेनॉल के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया कि यह आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही घरेलू कृषि और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन भी कर सकता है।

भारत वर्तमान में अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 87 प्रतिशत आयात करता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता बन जाती है।

सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को आक्रामक रूप से बढ़ाया है, मिश्रण का स्तर 2014 में 1.53 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 20 प्रतिशत हो जाएगा। गडकरी को एथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम के बड़े समर्थकों में से एक माना जाता है।

प्रस्तावित एथेनॉल आधारित स्टोव तकनीक इस दृष्टिकोण को घरेलू खाना पकाने के क्षेत्र तक विस्तारित करती है, जहां लाखों परिवार अभी भी एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर हैं। यदि इसे सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है और इसका व्यवसायीकरण किया जाता है, तो यह इनोवेशन पारंपरिक खाना पकाने वाली गैस का एक सस्ता, स्थानीय स्तर पर विकसित विकल्प प्रदान कर सकता है, साथ ही भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत कर सकता है। गडकरी ने कहा, 'जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, हम युवाओं और बच्चों में विज्ञान के प्रति प्रेम जगाने के लिए 40 करोड़ रुपए की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं। '

डाक विभाग का राजस्व 15.8 प्रतिशत बढ़कर 15,373 करोड़ रुपये पहुंचा, पार्सल सेवाओं में 70 प्रतिशत वृद्धि

एजेंसी

नई दिल्ली। डाक विभाग का राजस्व वित्त वर्ष 2025-26 में 15.8 प्रतिशत बढ़कर 15,373 करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष में विभाग का राजस्व लगभग 13,273 करोड़ रुपये था। इस वर्ष विभाग के राजस्व में 2,100 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पिछले कई वर्षों में औसतन 200 से 300 करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि होती रही थी। संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने इसे विभाग के 170 वर्ष के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बताया है।

डॉ. पेम्मासानी ने एक कार्यक्रम में जानकारी देते हुए कहा कि इंडिया पोस्ट की पार्सल और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में 70 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तकनीकी एकीकरण और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ साझेदारी के कारण विभाग की पार्सल सेवाओं में तेजी आई है। जब वर्तमान नेतृत्व ने कार्यभार संभाला था तब पार्सल सेवाओं से राजस्व लगभग 600

करोड़ रुपये था, जबकि अब इस क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये तक राजस्व क्षमता आंकी जा रही है। उन्होंने कहा कि ओटीपी आधारित डिलीवरी, एसएमएस ट्रैकिंग, यूपीआई और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं के कारण सेवाएं अधिक प्रभावी हुई हैं। विभाग ने मार्गों के पुनर्गठन के बाद छह महानगरों में 24 घंटे और 48 घंटे की स्पीड पोस्ट डिलीवरी सेवा भी शुरू की है। राज्य मंत्री ने कहा कि आईटी 2.0 के तहत एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी पहल में 5,800 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इसके तहत बचत योजनाओं और डाक जीवन बीमा सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि लोग बिना डाकघर गए ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें। नई व्यवस्था के तहत लोग एक क्लिक पर बचत योजनाएं और बीमा पॉलिसियां खरीद सकेंगे तथा परिपक्वता राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि डाक विभाग की बचत योजनाओं पर चार प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है, जो कई प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि आईटी 2.0 के तहत फेस रिकग्निशन, ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और राष्ट्रीय क्लाउड सुरक्षा मानकों जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी लागू की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से विभाग प्रतिवर्ष लगभग 45,000 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए वितरित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए डाक कर्मियों को मोबाइल फोन, बायोमेट्रिक उपकरण और प्रिंटर उपलब्ध कराए गए हैं।

भारत-कनाडा साल के अंत तक व्यापार समझौता वार्ता पूर्ण करने पर कर रहे विचार

एजेंसी

ओटावा। भारत और कनाडा ने आर्थिक संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में नई पहल का संकेत दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी करने पर विचार कर रहे हैं। गोयल ने विश्वास जताया कि दोनों देश 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को तीन गुना बढ़ाकर 50 अरब डॉलर तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही इस साल के अंत से पहले लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य भी रखा है। पीयूष गोयल ने मंगलवार को 'एक्स' पोस्ट पर लिखा कि दोनों देश व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। गोयल ने कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भारत की विकास यात्रा और बाजार में मौजूद बेहतरीन अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ओटावा में हुई साथर्क चर्चाओं की सराहना भी की और अर्थव्यवस्था व संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गहरे संबंध बनाने में भारतीय प्रवासियों के योगदान की तारीफ़ की। गोयल ने कहा कि मैंने भारत की असाधारण विकास यात्रा के बारे में बात की, जो यहां के लोगों की आकांक्षाओं, उद्यमशीलता की जीवंत भावना, विशाल प्रतिभा-भंडार और बाजार के व्यापक अवसरों से प्रेरित है। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के शीघ्र संपन्न होने को लेकर आशावाद भी व्यक्त किया। गोयल ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उनकी हाल की भारत यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया, जिसने भारत-कनाडा साझेदारी को एक नई गति और नया आत्मविश्वास प्रदान किया है।

सरकार लाएगी OFS: कोल इंडिया, एलआईसी समेत चार बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 27 की शुरुआती दो तिमाही में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी), इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) लाने की योजना बनाई है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार ने स्थिर बाजार में ओएफएस जारी करना चाहती है, जिससे शेयर की बिक्री के समय अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव के बचा जा सके। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सरकार कोल इंडिया में करीब दो प्रतिशत की हिस्सेदारी बेच सकती है। एलआईसी में ओएफएस वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही यानी

जुलाई-सितंबर अवधि में आ सकता है। आईओबी और आईआरएफसी में ओएफएस लाने पर सक्रिय बातचीत चल रही है और बाजार की स्थिरता का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 के संशोधित अनुमान 33,837 करोड़ रुपए से लगभग 135 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने गैर-कर राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में बड़े रणनीतिक विक्रय और ओएफएस का प्लान बनाया है। ओएफएस, उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसमें पैसा सीधे कंपनी के प्रमोटर के पास जाता है। सरकार विनिवेश के मोर्चे पर पहले से ही सक्रिय है, उसने दिसंबर 2025 में आईओबी में 2.17 प्रतिशत हिस्सेदारी और फरवरी 2026 में आईआरएफसी में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया था। इसके अलावा, सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की, जिसमें गैर-खुदरा बिक्री प्रस्ताव का हिस्सा 2.35 गुना सब्सक्राइब हुआ। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार के पास एक स्पष्ट परिभाषित पाइपलाइन द्वारा समर्थित 'एक बहुत मजबूत परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना' है। 'एक पाइपलाइन तैयार है, और सरकार को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। '

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, डर नहीं विश्वास जरूरी : वित्त मंत्री सीतारमण

एजेंसी

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है और कुछ लोग भारत में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे जनता का विश्वास कम होता है। उन्हें ऐसा करने के बजाय लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। सिडबी के फाउंडेशन डे कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में 'निराशावादी और संशयवादी दृष्टिकोण' फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आम नागरिकों की उपलब्धियों और योगदानों को अनुचित रूप से नजरअंदाज करता है। उन्होंने आगे कहा कि सभी हाई-फ्रीक्वेंसी इंटीकेटर्स दिखाते हैं कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। सितंबर 2025 में दरों में कटौती के बावजूद जीएसटी संग्रह मजबूत बना हुई है, जबकि खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में वाहन बिक्री और ऋण वृद्धि स्वस्थ बनी हुई है। सीतारमण ने सीआईआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सितंबर 2025 में निजी क्षेत्र के व्यय में सालाना आधार पर 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मार्च तिमाही में कंपनियों का लाभ मार्जिन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से ईंधन की ऊंची कीमतों, शिपिंग लागत में वृद्धि और निर्यात में व्यवधान के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है, हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की व्यापक आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है। सीतारमण ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव व्यवसायों के कार्यशील पूंजी चक्र को प्रभावित कर सकता है और निर्यात ऑर्डर को लेकर अनिश्चितता पैदा कर सकता है। उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक (सिडबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच एक को-लेंडिंग प्लेटफॉर्म सहित कई एमएसएमई-केंद्रित उपायों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ऋण पहुंच का विस्तार करना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सीजीटीएमएसई योजना के तहत एक विशेष माइक्रो क्रेडिट कार्ड शुरू किया है, जिससे उद्यम पोर्टल में पंजीकृत एमएसएमई 5 लाख रुपए तक के बिना गारंटी वाले ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी में बदलाव नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में तेजी का रुख नजर आ रहा है। हालांकि चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में आई तेजी के कारण चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर हिस्सों में सोना आज

320 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 340 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चेन्नई में सोने की कीमत में आज 520 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 570 रुपये प्रति 10 ग्राम तक का इजाफा हुआ है। भाव में आए उछाल के कारण देश के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,59,390 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,61,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना आज 1,46,110 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,47,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही बिक रही है।

बीएसएनएल का राजस्व दो वर्षों में 19 प्रतिशत बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये पहुंचा, ईबीआईटीडीए 7,000 करोड़ रुपये के करीब

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का राजस्व पिछले दो वर्षों में करीब 19 प्रतिशत बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि कंपनी का ब्याज, कर, मूल्यह्रास और अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत घटाने से पहले की कमाई (ईबीआईटीडीए) 50 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 7,000 करोड़ रुपये हो गया है। संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने एक कार्यक्रम में कहा कि स्वदेशी 4जी तकनीक, टावर और ग्रामीण कनेक्टिविटी विस्तार के कारण बीएसएनएल ने वित्तीय और परिचालन स्तर पर बड़ा सुधार दर्ज किया है। बीएसएनएल ने कार्य संस्कृति, टावरों की स्थिति और पुरानी अवसंरचना जैसी समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से दूर किया है। कंपनी ने निजी क्षेत्र जैसी जवाबदेही और लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले टावर अपटाइम केवल 75 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 95 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 50,000 टावरों में बैटरियां

बदली गईं, पावर प्लांट उन्नत किए गए और पुराने केबल बदले गए। साथ ही, प्रत्येक सर्किल और राज्य स्तर पर नए मोबाइल कनेक्शन और एंटरप्राइज कारोबार के लक्ष्य तय किए गए।

उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ने एक वर्ष के भीतर एक लाख टावरों पर स्वदेशी 4जी तकनीक शुरू की है। भारत अब गहरी स्वदेशी 4जी तकनीक विकसित करने वाले दुनिया के पांच देशों में शामिल हो गया है। डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए बीएसएनएल निजी कंपनियों की तुलना में सस्ती दरों पर सेवाएं दे रहा है। डाकघरों के माध्यम से एक रुपये के सिम कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट के जरिए घर-घर जाकर बीएसएनएल सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 35,000 गांव लंबे समय तक दूरसंचार सेवाओं से वंचित थे। अब तक लगभग 25,000 टावर लगाए जा चुके हैं और 10,000 अन्य टावरों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में बीएसएनएल टावर लगने से लोग तेजी से पुलिस और प्रशासन से संपर्क कर पा रहे हैं, जिससे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सुधारने में मदद मिली है। राज्य मंत्री ने बताया कि भारतनेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों तक उच्च गति फाइबर नेटवर्क पहुंचाने के लिए लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 15 लाख ग्रामीण घर जुड़े हैं और पहले चरण में 1.5 करोड़ घरों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में संचार अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में बीएसएनएल को 'विश्वसनीय, गर्व का विषय और लाभकारी' कंपनी बनाने का लक्ष्य है।

एलआईसी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.06 फीसदी की

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.06 फीसदी कर ली है। पहले यह हिस्सेदारी 3.16 फीसदी थी। सेंट्रल बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि एलआईसी ने 22 मई को बाजार खरीद के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता में 26.26 करोड़ शेयर यानी 2.90 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। इस अधिग्रहण के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़कर 6.06 फीसदी हो गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 0.03 फीसदी की गिरावट के साथ 31.29 रुपये पर बंद हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार की चार फीसदी हिस्सेदारी के लिए बिक्री पेशकश (ओएफएस) को संस्थागत निवेशकों से शुक्रवार को 2,380 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां मिलीं थीं।

खान सचिव ने खनिज ब्लॉक की नीलामी और उसके संचालन की प्रगति की समीक्षा की

नई दिल्ली। खान मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल ने खनिज ब्लॉक की नीलामी और उनके परिचालन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में नीलाम किए गए ब्लॉकों के संचालन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। खान मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि सचिव पीयूष गोयल ने मंत्रालय और श्रेणी-ए खनिज उत्पादक राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देशभर में खनिज ब्लॉकों की नीलामी और उनके संचालन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित नौवीं मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में खनन क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने, घरेलू खनिज उत्पादन बढ़ाने और नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंत्रालय के मुताबिक समीक्षा बैठक के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2015 में नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान कुल 108 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। इसके बाद नीलामी की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच 364 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई, जो प्रति वर्ष औसतन लगभग 90 ब्लॉक है।

उदय कोटक को बैंकिंग क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया पद्म भूषण सम्मान

नई दिल्ली। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय सुरेश कुमार कोटक को वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान न केवल उदय कोटक की व्यक्तिगत व्यावसायिक सफलता को दर्शाता है, बल्कि देश के व्यापार और उद्योग क्षेत्र की मजबूती और अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की भूमिका को भी सर्वोच्च स्तर पर मान्यता देता है। इसके अलावा वर्ष 2026 के लिए पद्मश्री पुरस्कार सोलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल, दास ऑफशोर इंजीनियरिंग के अशोक खाड़े और टीटीके ग्रुप के चेयरमैन टीटी जगन्नाथन (मरणोपरांत) को यह पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो देश के लिए की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा को मान्यता प्रदान करता है।

पेप्सिको का लेज मिनी स्टिक्स अब उत्तर और पश्चिम भारत में भी उपलब्ध

नई दिल्ली। पेप्सिको इंडिया ने अपने लोकप्रिय स्नैक ब्रांड 'लेज' का नया स्टिक-फॉर्मेट 'लेज मिनी स्टिक्स' का विस्तार अब उत्तर और पश्चिम भारत के बाजार में किया है। यह उत्पाद अब उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत के बाजारों में जनरल ट्रेड स्टोर्स पर 5 रुपये और 10 रुपये की किफायती कीमत में उपलब्ध है। पेप्सिको इंडिया का यह नया करारा स्टिक-फॉर्मेट स्नैक अब उन बाजारों में अपनी जगह बना रहा है, जहां हर बाइट में मसालों का स्वाद और साथ मिलकर खाने का मजा उपभोक्ताओं को खूब पसंद आता है। कंपनी ने इससे पहले पूर्वी भारत में लेज मिनी स्टिक्स की शानदार शुरुआत की थी। दशकों से लेज अपने आइकॉनिक आलू चिप्स और यादगार फ्लेवर अनुभवों के लिए जाना जाता रहा है, जिसने भारतभर के उपभोक्ताओं के स्नैकिंग पलों को खास बनाया है। लेज मिनी स्टिक्स के साथ पेप्सिको इंडिया ब्रांड ने अपने लोकप्रिय आलू स्नैकिंग अनुभव को नए स्टिक फॉर्मेट में पेश किया है, जो परिचित नमकीन स्वाद के साथ मजेदार और करारे क्रंच का नया ट्विस्ट लेकर आया है। लॉन्च के बारे में बात करते हुए मुख्य विपणन अधिकारी, फूड्स, पेप्सिको इंडिया, साक्षी वर्मा मेनन ने कहा, 'पेप्सिको इंडिया में हमारी विकास रणनीति हमेशा उपभोक्ताओं की पसंद और बदलती जरूरतों को समझने पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि भारत में स्नैकिंग का तरीका तेजी से बदल रहा है, जहां भागदौड़ भरी इस जीवनशैली के बीच लोग ऐसे स्नैक्स चाहते हैं, जिन्हें कहीं भी और कभी भी आसानी से आनंद लिया जा सके। ऐसे में आलू चिप्स श्रेणी में अग्रणी ब्रांड होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बदलाव के साथ चलने की नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की भी है। लेज मिनी स्टिक्स हमारे इसी 'इनोवेशन-फर्स्ट' विज़न का बेहतरीन उदाहरण है।

तेलंगाना ने एलएंडटी से खरीदी हैदराबाद मेट्रो, आईआरएफसी से लिया 13,527 करोड़ रु. का ऋण

एजेंसी

नई दिल्ली । तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो का लार्सन एंड टूब्रो मेट्रो रेल लिमिटेड से अधिग्रहण कर लिया है और इसके लिए रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) से साढ़े 13 हजार करोड़ रुपये का किफायती ऋण लिया है। आईआरएफसी ने यहां एलएंडटी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड के साथ 13,527 करोड़ रुपये के एक ऐतिहासिक टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईआरएफसी के सीएमडी एवं सीईओ मनोज कुमार दुबे तथा तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह पुनर्वित्तपोषण एलएंडटी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड के 100 प्रतिशत स्वामित्व को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड

से हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के माध्यम से तेलंगाना सरकार को हस्तांतरित किए जाने के बाद किया जा रहा है। इस हस्तांतरण के बाद अब हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन परिसंपत्ति बन गया है, जिससे देश के शहरी परिवहन क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण पुनर्वित्त (रिफाइनेंसिंग) लेन-देन में से एक माना जा रहा है। दुबे के अनुसार इस सौदे में ऋण की राशि 13,527 करोड़ रुपये होगी। ऋण की अवधि 20 वर्ष होगी और इसे त्रैमासिक भुगतान संरचना के साथ चुकता किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना की ऋण देनदारियों के पुनर्वित्तपोषण की परियोजना प्रोसेसिंग फीस, कमिटमेंट चार्ज या प्री-पेमेंट पेनल्टी से पूरी तरह मुक्त होगी। इस सौदे के बारे में दुबे ने कहा कि इस लेन-देन को बेहद मजबूत सुरक्षा ढांचा प्रदान किया गया है। इसके तहत तेलंगाना सरकार द्वारा आईआरएफसी के सभी भुगतानों के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय आश्वासन, राज्य सरकार की गारंटी तथा रिजर्व बैंक समर्थित डायरेक्ट डेबिट मैकेनिज्म शामिल हैं। मनोज कुमार दुबे ने कहा, यह लेन-देन दर्शाता है कि बड़े पैमाने की शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को भारत में ही दीर्घावधि और कुशल वित्तीय संरचनाओं के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है।

अब सीएनजी की कीमत बढ़ी, दिल्ली में हुई प्रति किलोग्राम 83.09 रुपये

एजेंसी

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के ठीक एक दिन बाद आज सीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया है। आज से सीएनजी की दर 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है। 15 मई के बाद यह चौथी बढ़ोतरी है। इस बदलाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

इससे पहले सीएनजी की कीमत में 15 मई को 2 रुपये, 18 मई को 1 रुपया, और 23 मई को 1 रुपया की बढ़ोतरी की गई थई। इसका असर सबसे अधिक दिल्ली-एनसीआर में देखने को मिल सकता है। यहां ऑटो, टैक्सी, स्कूल वैन और प्राइवेट कारों में सीएनजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि से परिवहन लागत और घरेलू बजट पर दबाव बढ़ने की आशंका है यह वृद्धि मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण देखने को मिल रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों का

आवागमन प्रभावित है। मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच करीब 12 हफ्ते से टकराव जारी है। इस कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। कल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल के बाद इस साल पहली बार कीमतें 100 रुपये के पार चली गईं।

आगामी खरीफ सत्र के लिए देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता: सरकार

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा कि आगामी खरीफ सत्र के लिए देश में उर्वरकों की उपलब्धता के साथ इनकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार ने कहा कि खरीफ सत्र के लिए कुल आवश्यकता 390.54 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) आंकी गई है, जिसके मुकाबले में 200.12 एलएमटी का स्टॉक उपलब्ध है।

उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद उर्वरकों का घरेलू उत्पादन अच्छा रहा है, और इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयात भी किया जा रहा है। अतिरिक्त सचिव, अपर्णा एस. शर्मा ने कहा कि इस साल के लिए 390.54 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के अनुमान के मुकाबले देश में उर्वरकों की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मौजूदा स्टॉक 200.12 लाख मीट्रिक टन है, जो 51 फीसदी से

अधिक है और सामान्य स्तर 33 फीसदी से काफी अधिक है।अपर्णा एस. शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद घरेलू उत्पादन और उर्वरक आयात काफी ज्यादा रहा है। उन्होंने कहा कि कुल घरेलू उत्पादन लगभग 95 लाख मीट्रिक टन रहा है, और करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयात हमारे देश में पहुंचा है। इस तरह कुल मिलाकर समग्र उपलब्धता में 117.6 लाख मीट्रिक टन उर्वरक जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि देश ने 13.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 9 लाख मीट्रिक टन एनपीके कॉम्प्लेक्स भी हासिल किए हैं, जो खरीफ मौसम के चरम समय के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

एथेनॉल आधारित स्टोव पर खाना बनाने की लागत एलपीजी से कम : नितिन गडकरी

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल आधारित स्वदेशी कुकिंग स्टोव टेक्नोलॉजी का अनावरण किया और कहा कि इस स्वदेशी स्टोव पर कमर्शियल एलपीजी की तुलना में कम कीमत पर खाना बनाया जा सकता है। साथ ही, उन्होंने युवा भारतीयों की विज्ञान में रुचि को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपए की एक पहल की घोषणा भी की। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि नई तकनीक में खाना पकाने के लिए उपयुक्त लौ उत्पन्न करने के लिए एथेनॉल और पानी के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। मंत्री ने कहा, 'पानी में 7 प्रतिशत एथेनॉल मिलाकर स्टोव से लौ उत्पन्न की जा सकती है, और यह खाना पकाने वाली गैस से सस्ती है। यह हमारे देश में ही विकसित की गई है। ' यह घोषणा जीवाश्म ईंधन के टिकाऊ और किफायती विकल्प के रूप में एथेनॉल के लिए गडकरी के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के अनुरूप है। पिछले कई वर्षों से, उन्होंने परिवहन और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में यह तर्क देते हुए एथेनॉल के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया कि यह आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही घरेलू कृषि और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन भी कर सकता है।

भारत वर्तमान में अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 87 प्रतिशत आयात करता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता बन जाती है।

सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को आक्रामक रूप से बढ़ाया है, मिश्रण का स्तर 2014 में 1.53 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 20 प्रतिशत हो जाएगा। गडकरी को एथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम के बड़े समर्थकों में से एक माना जाता है।

प्रस्तावित एथेनॉल आधारित स्टोव तकनीक इस दृष्टिकोण को घरेलू खाना पकाने के क्षेत्र तक विस्तारित करती है, जहां लाखों परिवार अभी भी एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर हैं। यदि इसे सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है और इसका व्यवसायीकरण किया जाता है, तो यह इनोवेशन पारंपरिक खाना पकाने वाली गैस का एक सस्ता, स्थानीय स्तर पर विकसित विकल्प प्रदान कर सकता है, साथ ही भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत कर सकता है। गडकरी ने कहा, 'जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, हम युवाओं और बच्चों में विज्ञान के प्रति प्रेम जगाने के लिए 40 करोड़ रुपए की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं। '

डाक विभाग का राजस्व 15.8 प्रतिशत बढ़कर 15,373 करोड़ रुपये पहुंचा, पार्सल सेवाओं में 70 प्रतिशत वृद्धि

एजेंसी

नई दिल्ली। डाक विभाग का राजस्व वित्त वर्ष 2025-26 में 15.8 प्रतिशत बढ़कर 15,373 करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष में विभाग का राजस्व लगभग 13,273 करोड़ रुपये था। इस वर्ष विभाग के राजस्व में 2,100 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पिछले कई वर्षों में औसतन 200 से 300 करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि होती रही थी। संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने इसे विभाग के 170 वर्ष के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बताया है।

डॉ. पेम्मासानी ने एक कार्यक्रम में जानकारी देते हुए कहा कि इंडिया पोस्ट की पार्सल और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में 70 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तकनीकी एकीकरण और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ साझेदारी के कारण विभाग की पार्सल सेवाओं में तेजी आई है। जब वर्तमान नेतृत्व ने कार्यभार संभाला था तब पार्सल सेवाओं से राजस्व लगभग 600

करोड़ रुपये था, जबकि अब इस क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये तक राजस्व क्षमता आंकी जा रही है। उन्होंने कहा कि ओटीपी आधारित डिलीवरी, एसएमएस ट्रैकिंग, यूपीआई और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं के कारण सेवाएं अधिक प्रभावी हुई हैं। विभाग ने मार्गों के पुनर्गठन के बाद छह महानगरों में 24 घंटे और 48 घंटे की स्पीड पोस्ट डिलीवरी सेवा भी शुरू की है। राज्य मंत्री ने कहा कि आईटी 2.0 के तहत एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी पहल में 5,800 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इसके तहत बचत योजनाओं और डाक जीवन बीमा सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि लोग बिना डाकघर गए ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें। नई व्यवस्था के तहत लोग एक क्लिक पर बचत योजनाएं और बीमा पॉलिसियां खरीद सकेंगे तथा परिपक्वता राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि डाक विभाग की बचत योजनाओं पर चार प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है, जो कई प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि आईटी 2.0 के तहत फेस रिकग्निशन, ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और राष्ट्रीय क्लाउड सुरक्षा मानकों जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी लागू की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से विभाग प्रतिवर्ष लगभग 45,000 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए वितरित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए डाक कर्मियों को मोबाइल फोन, बायोमेट्रिक उपकरण और प्रिंटर उपलब्ध कराए गए हैं।

भारत-कनाडा साल के अंत तक व्यापार समझौता वार्ता पूर्ण करने पर कर रहे विचार

एजेंसी

ओटावा। भारत और कनाडा ने आर्थिक संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में नई पहल का संकेत दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी करने पर विचार कर रहे हैं। गोयल ने विश्वास जताया कि दोनों देश 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को तीन गुना बढ़ाकर 50 अरब डॉलर तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही इस साल के अंत से पहले लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य भी रखा है। पीयूष गोयल ने मंगलवार को 'एक्स' पोस्ट पर लिखा कि दोनों देश व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। गोयल ने कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भारत की विकास यात्रा और बाजार में मौजूद बेहतरीन अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ओटावा में हुई सार्थक चर्चाओं की सराहना भी की और अर्थव्यवस्था व संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गहरे संबंध बनाने में भारतीय प्रवासियों के योगदान की तारीफ़ की। गोयल ने कहा कि मैंने भारत की असाधारण विकास यात्रा के बारे में बात की, जो यहां के लोगों की आकांक्षाओं, उद्यमशीलता की जीवंत भावना, विशाल प्रतिभा-भंडार और बाजार के व्यापक अवसरों से प्रेरित है। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के शीघ्र संपन्न होने को लेकर आशावाद भी व्यक्त किया। गोयल ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उनकी हाल की भारत यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया, जिसने भारत-कनाडा साझेदारी को एक नई गति और नया आत्मविश्वास प्रदान किया है।

सरकार लाएगी OFS: कोल इंडिया, एलआईसी समेत चार बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 27 की शुरुआती दो तिमाही में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी), इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) लाने की योजना बनाई है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार ने स्थिर बाजार में ओएफएस जारी करना चाहती है, जिससे शेयर की बिक्री के समय अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव के बचा जा सके। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सरकार कोल इंडिया में करीब दो प्रतिशत की हिस्सेदारी बेच सकती है। एलआईसी में ओएफएस वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही यानी

जुलाई-सितंबर अवधि में आ सकता है। आईओबी और आईआरएफसी में ओएफएस लाने पर सक्रिय बातचीत चल रही है और बाजार की स्थिरता का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 के संशोधित अनुमान 33,837 करोड़ रुपए से लगभग 135 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने गैर-कर राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में बड़े रणनीतिक विक्रय और ओएफएस का प्लान बनाया है। ओएफएस, उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसमें पैसा सीधे कंपनी के प्रमोटर के पास जाता है। सरकार विनिवेश के मोर्चे पर पहले से ही सक्रिय है, उसने दिसंबर 2025 में आईओबी में 2.17 प्रतिशत हिस्सेदारी और फरवरी 2026 में आईआरएफसी में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया था। इसके अलावा, सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की, जिसमें गैर-खुदरा बिक्री प्रस्ताव का हिस्सा 2.35 गुना सब्सक्राइब हुआ। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार के पास एक स्पष्ट परिभाषित पाइपलाइन द्वारा समर्थित 'एक बहुत मजबूत परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना' है। 'एक पाइपलाइन तैयार है, और सरकार को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। '

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, डर नहीं विश्वास जरूरी : वित्त मंत्री सीतारमण

एजेंसी

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है और कुछ लोग भारत में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे जनता का विश्वास कम होता है। उन्हें ऐसा करने के बजाय लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। सिडबी के फाउंडेशन डे कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में 'निराशावादी और संशयवादी दृष्टिकोण' फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आम नागरिकों की उपलब्धियों और योगदानों को अनुचित रूप से नजरअंदाज करता है। उन्होंने आगे कहा कि सभी हाई-फ्रीक्वेंसी इंटीकेटर्स दिखाते हैं कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। सितंबर 2025 में दरों में कटौती के बावजूद जीएसटी संग्रह मजबूत बना हुई है, जबकि खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में वाहन बिक्री और ऋण वृद्धि स्वस्थ बनी हुई है। सीतारमण ने सीआईआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सितंबर 2025 में निजी क्षेत्र के व्यय में सालाना आधार पर 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मार्च तिमाही में कंपनियों का लाभ मार्जिन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से ईंधन की ऊंची कीमतों, शिपिंग लागत में वृद्धि और निर्यात में व्यवधान के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है, हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की व्यापक आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है। सीतारमण ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव व्यवसायों के कार्यशील पूंजी चक्र को प्रभावित कर सकता है और निर्यात ऑर्डर को लेकर अनिश्चितता पैदा कर सकता है। उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक (सिडबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच एक को-लेंडिंग प्लेटफॉर्म सहित कई एमएसएमई-केंद्रित उपायों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ऋण पहुंच का विस्तार करना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सीजीटीएमएसई योजना के तहत एक विशेष माइक्रो क्रेडिट कार्ड शुरू किया है, जिससे उद्यम पोर्टल में पंजीकृत एमएसएमई 5 लाख रुपए तक के बिना गारंटी वाले ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी में बदलाव नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में तेजी का रुख नजर आ रहा है। हालांकि चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में आई तेजी के कारण चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर हिस्सों में सोना आज

320 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 340 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चेन्नई में सोने की कीमत में आज 520 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 570 रुपये प्रति 10 ग्राम तक का इजाफा हुआ है। भाव में आए उछाल के कारण देश के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,59,390 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,61,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना आज 1,46,110 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,47,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही बिक रही है।

बीएसएनएल का राजस्व दो वर्षों में 19 प्रतिशत बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये पहुंचा, ईबीआईटीडीए 7,000 करोड़ रुपये के करीब

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का राजस्व पिछले दो वर्षों में करीब 19 प्रतिशत बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि कंपनी का ब्याज, कर, मूल्यह्रास और अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत घटाने से पहले की कमाई (ईबीआईटीडीए) 50 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 7,000 करोड़ रुपये हो गया है। संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने एक कार्यक्रम में कहा कि स्वदेशी 4जी तकनीक, टावर और ग्रामीण कनेक्टिविटी विस्तार के कारण बीएसएनएल ने वित्तीय और परिचालन स्तर पर बड़ा सुधार दर्ज किया है। बीएसएनएल ने कार्य संस्कृति, टावरों की स्थिति और पुरानी अवसंरचना जैसी समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से दूर किया है। कंपनी ने निजी क्षेत्र जैसी जवाबदेही और लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले टावर अपटाइम केवल 75 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 95 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 50,000 टावरों में बैटरियां

बदली गईं, पावर प्लांट उन्नत किए गए और पुराने केबल बदले गए। साथ ही, प्रत्येक सर्किल और राज्य स्तर पर नए मोबाइल कनेक्शन और एंटरप्राइज कारोबार के लक्ष्य तय किए गए।

उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ने एक वर्ष के भीतर एक लाख टावरों पर स्वदेशी 4जी तकनीक शुरू की है। भारत अब गहरी स्वदेशी 4जी तकनीक विकसित करने वाले दुनिया के पांच देशों में शामिल हो गया है। डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए बीएसएनएल निजी कंपनियों की तुलना में सस्ती दरों पर सेवाएं दे रहा है। डाकघरों के माध्यम से एक रुपये के सिम कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट के जरिए घर-घर जाकर बीएसएनएल सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 35,000 गांव लंबे समय तक दूरसंचार सेवाओं से वंचित थे। अब तक लगभग 25,000 टावर लगाए जा चुके हैं और 10,000 अन्य टावरों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में बीएसएनएल टावर लगने से लोग तेजी से पुलिस और प्रशासन से संपर्क कर पा रहे हैं, जिससे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सुधारने में मदद मिली है। राज्य मंत्री ने बताया कि भारतनेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों तक उच्च गति फाइबर नेटवर्क पहुंचाने के लिए लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 15 लाख ग्रामीण घर जुड़े हैं और पहले चरण में 1.5 करोड़ घरों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में संचार अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में बीएसएनएल को 'विश्वसनीय, गर्व का विषय और लाभकारी' कंपनी बनाने का लक्ष्य है।

page 1 and 8 may 27_page 1 Mar 25 final ds.qxd 5/27/2026 12:06 AM Page 2

शिवराज सिंह की पुस्तक 'अपनापन' का लोकार्पण, वेंकैया नायडू सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद

नई दिल्ली, 26 मई (हि.स.)। पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को एक समारोह में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक 'अपनापन' का लोकार्पण किया। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, कार्यशैली और उनके साथ बिताए गए 35 वर्षों के अनुभवों पर लिखी है। पुस्तक के लोकार्पण अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।

समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि जब कभी प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा होती थी, तब वे कहा करते थे कि मोदी का अर्थ है मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया और आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें यह भाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान विश्व मंच पर अधिक सशक्त हुई है। वेंकैया नायडू ने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय सभ्यता, भारतीयता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को वैश्विक स्तर पर नई स्वीकृति मिली है।

पद्म पुरस्कारों का उल्लेख कर वेंकैया नायडू ने कहा कि पहले ऐसे सम्मानों को अक्सर कुछ चुनिंदा प्रतिष्ठित वर्गों तक सीमित समझा जाता था लेकिन

अब प्रधानमंत्री मोदी की सोच रिकॉग्नाइज द अनरिकॉग्नाइज्ड की है, यानी उन साधारण लोगों को भी सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने चुपचाप समाज और राष्ट्र के लिए असाधारण योगदान दिया है। उन्होंने विशेष प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब किसानों जैसे मेहनतकश लोगों को भी राष्ट्रीय सम्मान मिलने लगे हैं और यह बदलती सोच भारत के सामाजिक सम्मान-क्रम को अधिक न्यायपूर्ण बनाती है। यह नेतृत्व का वही रूप है जो राष्ट्र निर्माण में सामान्य जन की भूमिका को केंद्र में रखता है।

वेंकैया नायडू ने रोचक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि जब वरिष्ठ नेता अनौपचारिक चर्चा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर विचार कर रहे थे, तब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम सुझाया था। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की सामूहिक सहमति से लिया गया यह निर्णय पूरी तरह सही सिद्ध हुआ।

वेंकैया नायडू ने कहा कि उस समय कुछ लोगों को आशंका थी कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान को कठिनाई हो सकती है लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार, सादगी, सेवा और संवाद से सबका विश्वास जीत लिया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और परिवारों के बीच गहरा भरोसा अर्जित किया और 'लाडली लक्ष्मी योजना' जैसी पहल उनके जन-संवेदनशील नेतृत्व का बड़ा उदाहरण बनी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें 卐मामा卐 कहती है और यह संबोधन केवल लोकप्रियता का नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और संरक्षण के भाव का प्रतीक है। किसी नेता को जनता अगर रिश्ते के नाम से पुकारे तो वह उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक पूंजी होती है।

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा गाँवों, खेतों, श्रम और साधारण जन के जीवनानुभवों से बनती है इसलिए ऐसा नेतृत्व सबसे अधिक प्रभावशाली होता है जो इस धरातल को समझता हो। कोई भी व्यक्ति तभी जननेता बनता है जब वह जनता की भाषा, उनकी चिंता और उनके जीवन-संघर्ष को भीतर से महसूस करता हो। उन्होंने 'अपनापन' को नेतृत्व के उसी जीवंत, मानवीय और लोकाभिमुख स्वरूप का विस्तार बताया।

देवेगौड़ा ने यह भी कहा कि किसी सार्वजनिक व्यक्तित्व की वास्तविक ताकत उसके भीतर की करुणा, धैर्य और सेवाभाव में होती है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि किसी बड़े नेता को समझने के लिए केवल उसकी उपलब्धियां देखना पर्याप्त नहीं होता; यह भी देखना आवश्यक है कि वह सामान्य कार्यकर्ता, किसान, गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। उनके वक्तव्य में यह भाव उभरकर आया कि 'अपनापन' नेतृत्व का वह गुण है जो व्यक्ति को भीड़ में अलग बनाता है और जनसामान्य को यह अनुभव कराता है कि सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति भी उनके जीवन की धड़कनों से जुड़ा है।

स्थानीय समाचार

मुख्यमंत्री उमर ने ईद-उल-अधा के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं

श्रीनगर, 26 मई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को ईद-उल-अधा के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और शांति, समृद्धि और खुशियों की कामना की। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद-उल-अधा त्याग, करुणा, उदारता और सर्वशक्तिमान अल्लाह में पूर्ण विश्वास के मूल्यों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह पवित्र अवसर लोगों को भाईचारे, दयालुता और मानवता की निस्वार्थ सेवा की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है।

हजरत इब्राहिम (एएस) के सर्वोच्च बलिदान और हजरत इस्माइल (एएस) की अटूट भक्ति को याद करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी विरासत मानवता को धार्मिकता, धैर्य और अल्लाह की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता की ओर मार्गदर्शन करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार जम्मू और कश्मीर में सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी सम्मान और सामाजिक एकता को और मजबूत करेगा।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ईद के उत्सव के दौरान गरीबों, जरूरतमंदों और वंचितों को याद रखें और उनके साथ ईद की खुशियां बांटें। उमर अब्दुल्ला ने लोगों के लिए स्थायी शांति, खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की और आशा व्यक्त की कि यह शुभ अवसर हर घर में खुशी और आशीर्वाद लेकर आए।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कौशल कुमार शर्मा को लद्दाख के डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया

लेह, 26 मई (हि.स.)। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी कौशल कुमार शर्मा को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है।गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार शर्मा जो वर्तमान में लेह-कारगिल रेंज के डीआईजी के पद पर कार्यरत हैं, एक स्थायी अधिकारी की नियुक्ति होने तक इस शीर्ष पद पर बने रहेंगे। यह निर्णय वर्तमान डीजीपी मुकेश सिंह (आईपीएस, 1996 बैच) को कार्यमुक्त किए जाने के बाद लिया गया है।

सिंह को 27 मई, 2026 से लद्दाख में आधिकारिक तौर पर कार्यमुक्त कर दिया गया है और उन्हें मणिपुर सरकार को अपनी अगली नियुक्ति के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

जाविद डार ने ईद-उल-अजहा पर लोगों को दी शुभकामनाएं, शांति और समृद्धि की कामना की

श्रीनगर, मई 26। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव विभाग के मंत्री जाविद अहमद डार ने पवित्र ईद-उल-अजहा के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

मंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह पर्व समाज में सद्भाव, करुणा और शांति को और मजबूत करेगा।

अपने संदेश में मंत्री ने कहा कि ईद-उल-अजहा त्याग, उदारता, सहानुभूति और समर्पण जैसे शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व एकता, भाईचारे और आपसी सम्मान के महत्व को समझने तथा समाज के सभी वर्गों में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, यह पवित्र पर्व हर घर में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए तथा हमारे जीवन को आशा, सकारात्मकता और करुणा से रोशन करे।

मंत्री ने लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और निरंतर सफलता की भी कामना की। उन्होंने लोगों से प्रेम, साझेदारी और करुणा की भावना के साथ त्योहार मनाने तथा जरूरतमंद और वंचित वर्गों की सहायता करने की अपील की।

उपमुख्यमंत्री ने ईद-उल-अजहा की शुभकामनाएं दी

श्रीनगर, मई 26। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज जम्मू-कश्मीर के लोगों को ईद-उल-अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

इस पावन अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व दुनियाभर के मुसलमानों के लिए अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है तथा जम्मू-कश्मीर में इसे पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि यह पर्व त्याग, अनुशासन, समर्पण और सर्वशक्तिमान की इच्छा के प्रति पूर्ण आस्था का प्रतीक है तथा लोगों को करुणा, उदारता और भाईचारे के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर हमेशा आपसी समझ, सांप्रदायिक सौहार्द और सभी धर्मों के सम्मान का प्रतीक रहा है। यहां के लोगों ने हमेशा भाईचारे, प्रेम और एकजुटता की भावना को बनाए रखा है।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और प्रगति की प्रार्थना की।

नशा मुक्ति अभियान के तहत कठुआ में मेडिकल स्टोर सील, कई खामियां उजागर

कठुआ, 26 मई (हि.स.)। नशा मुक्ति जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत कठुआ में मंगलवार को ड्रग्स विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने न्यू बस स्टैंड के पास एक मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया।

संयुक्त ऑपरेशन के दौरान टीम ने महादेव मेडिकोज नामक दुकान की जांच की जिसमें 4 से 5 गंभीर खामियां पाई गईं। अधिकारियों के अनुसार दुकान में दवाइयों का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा था, कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध नहीं थे या कार्यरत नहीं थे तथा साफ-सफाई की स्थिति भी बेहद खराब पाई गई।

अधिकारियों ने बताया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दुकान को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक सभी कमियां दूर कर सही रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जाता। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक जिले में करीब 150 मेडिकल दुकानों की जांच की जा चुकी है और मंगलवार को भी 4-5 दुकानों की जांच की गई। ड्रग्स विभाग ने अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सभी दुकानदार नियमों का पालन करें, रिकॉर्ड सही रखें और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी।

नगरी में विकास कार्यों का लोकार्पण, बाढ़ प्रभावित परिवारों को मदद का आश्वासन

कठुआ, 26 मई (हि.स.)। कठुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण ने नगरी क्षेत्र में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया जिनका उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

उद्घाटन किए गए कार्यों में नक्कियां-नगरी रोड पर दो पुलिया, नगर समिति नगरी के वार्ड नंबर 7 में एक लेन तथा वार्ड नंबर 5 में ड्रेनेज निर्माण कार्य शामिल हैं। इन सभी कार्यों पर करीब 15 लाख रुपये की लागत आई है जिससे सड़क संपर्क और जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा। दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने अगस्त 2025 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए सात परिवारों के घरों की समस्या विधायक के सामने रखी। डॉ. भारत भूषण ने प्रत्येक घर का दौरा कर आश्वासन दिया कि पात्रता की जांच के बाद इन परिवारों को पीएमएवाई पैटर्न के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। लोगों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि कठुआ विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और

हर गांव व वार्ड तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने सड़कों, जल निकासी, पानी की आपूर्ति सहित अन्य समस्याएं भी उठाईं जिनके शीघ्र समाधान का भरोसा विधायक ने दिलाया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने विकास कार्यों की सराहना की।

जंगलोट दौरे पर विधायक, जल संकट समाधान को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

कठुआ, 26 मई (हि.स.)। कठुआ के विधायक डॉ भारत भूषण ने जंगलोट गांव और जंगलोट वेस्ट के विभिन्न वार्डों का विस्तृत दौरा कर स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी, विकास कार्यों की जरूरत और अन्य समस्याएं विधायक के समक्ष रखीं। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि सभी जायज मांगों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के विकास के लिए वे पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और कठुआ विधानसभा क्षेत्र का कोई भी इलाका विकास से वंचित नहीं रहेगा। लोगों से बातचीत के दौरान विधायक ने विशेष रूप से गर्मियों में बढ़ते जल संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसे दूर करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

अमरनाथ यात्रा-2026-एनएच पर लंगर स्थलों की सुरक्षा का एसएसपी कठुआ ने लिया जायजा, सख्त निर्देश जारी

कठुआ, 26 मई (हि.स.)। पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से एसएसपी कठुआ मोहीता शर्मा ने मंगलवार को जिले के नेशनल हाईवे पर स्थापित सभी लंगर स्थलों, जिनमें लखनपुर भी शामिल है, का व्यापक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान एसएसपी के साथ सभी क्षेत्राधिकार अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने यात्रा मार्ग पर बनाए गए प्रत्येक लंगर स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया।

इस दौरान एसएसपी ने मौके पर ही अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि वार्षिक यात्रा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

उन्होंने सीसीटीवी, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े इंतजामों की भी समीक्षा की। साथ ही सभी लंगर प्रबंधन समितियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करें जिसमें कैमरों की स्थापना, पर्याप्त पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं।

कठुआ पुलिस ने दोहराया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, सहज और परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अब नहीं मानेंगे आश्वासन-कठुआ में सफाई कर्मियों की सख्त चेतावनी के साथ हड़ताल शुरू

कठुआ, 26 मई (हि.स.)। नगर परिषद कठुआ के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मंगलवार से हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने नगर परिषद परिसर में एकत्र होकर लोकल बॉडी डायरेक्टर और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उठाया।

सफाई कर्मचारियों के प्रधान ने बताया कि उनकी स्थायीकरण की मांग वर्ष 2014 से लंबित है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कई चुनावों के दौरान उन्हें केवल आश्वासन ही मिला जबकि उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बार वे झूठे आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक उन्हें स्थायी नहीं किया जाता, हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों ने डेली वेजर्स को नियमित करने और सफाई कर्मचारियों की कमी को जल्द पूरा करने की भी मांग की।

प्रधान ने बताया कि नगर परिषद में कुल 112 कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं जबकि 21 वार्डों के लिए पर्याप्त सफाई कर्मचारी नहीं हैं। इसके बावजूद शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारियों ने कहा कि वे हड़ताल नहीं करना चाहते क्योंकि इससे शहर में गंदगी फैलती है लेकिन लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए समर्पित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने की वकालत की

कांगड़ा, मई 26। हिमाचल प्रदेश की अपार आध्यात्मिक और पर्यटन संभावनाओं पर जोर देते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए एक समर्पित और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस सर्किट के माध्यम से राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों, शक्तिपीठों, मठों और पवित्र स्थलों को बेहतर बुनियादी ढांचे, मजबूत संपर्क व्यवस्था और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल राज्य की आध्यात्मिक पहचान मजबूत होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का संरक्षण भी होगा।

राज्यपाल ने यह बातें आज कांगड़ा जिले में स्थित पवित्र मां ज्वाला देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं। इस अवसर पर उनके साथ प्रथम महिला श्रीमती बिंदु गुप्ता भी मौजूद रहीं।

इस दौरान श्री कविंदर गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश और पूरे देश के लोगों की शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की तथा मां ज्वाला देवी से देशभर में सुख, शांति और सौहार्द बनाए रखने का आशीर्वाद मांगा।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है, जहां ज्वाला देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, चामुंडा देवी सहित कई प्राचीन मंदिर और मठ स्थित हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी पवित्र स्थलों को एक व्यापक धार्मिक पर्यटन सर्किट के अंतर्गत जोड़ने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके और दुनिया भर से अधिक से अधिक भक्त यहां आकर्षित हों।

एलजी विनय कुमार सक्सेना ने शम जिले के गठन पर आयोजित समारोह में भाग लिया

लेह, मई 26। उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना ने आज खलत्से का दौरा किया और लद्दाख में शम को नए जिले के रूप में बनाए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। नए जिले के गठन के बाद यह एल-जी का शम का पहला दौरा था। खलत्से, जो अब जिला मुख्यालय है, पहुंचने पर ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, छात्रों, सांस्कृतिक दलों और नागरिक समाज के सदस्यों ने पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया।

शम जिले का गठन 27 अप्रैल 2026 को उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिलों के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद हुआ। शम जिले में कुल 27 राजस्व गांव शामिल हैं, जिनमें 5 गांव कारगिल जिले से और 22 गांव लेह जिले से शामिल किए गए हैं। इस अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने लोगों को उनकी लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नए जिले का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लद्दाख तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के प्रति विशेष ध्यान और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।एल-जी श्री सक्सेना ने कहा कि नए जिले के गठन से शासन और सार्वजनिक सेवाएं अब लोगों के घर-द्वार तक अधिक सुलभ और प्रभावी बनेंगी। उन्होंने कहा कि शम जिला प्रशासन और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करेगा, जिससे सेवाओं की तेज डिलीवरी और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित होगा। शम को लद्दाख की खुबानी घाटी बताते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि यहां उगाई जाने वाली जीआई टैग प्राप्त रक्तसे कारपो खुबानी किस्म अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में लगभग 1000 मीट्रिक टन ताजा खुबानी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात की जाएगी, जो लद्दाख के बागवानी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विभिन्न संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से खुबानी की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहायता करेगा, ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके।

कहा, नए जिले के गठन से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेगा और पश्चिमी लद्दाख के विकास को मिलेगी गति

श्री सक्सेना ने आगे बताया कि हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के साथ हुई बैठक में लद्दाख में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहयोग का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से विशेष रूप से शम क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा, जो खुबानी और सेब के प्रमुख उत्पादक हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि नए जिले के गठन से स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी विभागों में नए पद सृजित होने के साथ-साथ निर्माण, परिवहन, व्यापार, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में भी अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।